वर्ष : 42; अंक : 11 ; नवम्बर 2020;

(ई–संस्करण)

सीटू मजदूर

सीटू ने 7 नवम्बर, 2020 को मनाया

- मजदूर वर्ग के नेतृत्व में अक्टूबर क्रान्ति का 104वां वर्ष
- भारत में पहले ट्रेड यूनियन केंद्र की स्थापना की शताब्दि
- सीटू की स्थापना की स्वर्णजियंती

सीटू के राष्ट्रीय नेताओं का ऑनलाइन सम्बोधन

हेमलता

तपन सेन

इलामारन करीम

सुभाष मुखर्जी

ए. सौन्दराजन

एम सांईबाबू

मीनाक्षी सुन्दरम

शोक संवेदना

कामरेड मारुति मनपडे

सोलापुर में कामरेड मारुति मनपडे, जो एआईकेएस कर्नाटक राज्य इकाई के उपाध्यक्ष, और पूर्व अध्यक्ष, और कर्नाटक ग्राम पंचायत वर्कर्स यूनियन (सीटू) के अध्यक्ष भी थे, के अचानक निधन पर सीटू को सदमा लगा है और षोक हुआ है।

भूमि अधिकारों, गन्ना और अन्य किसानों की मांगों के लिए कई संघर्षों में वह अग्रिम पंक्ति में थे; उन्होंने पंचायत, मनरेगा और अन्य मजदूरों को संगठित करने में मदद की; प्रारंभिक चरणों में आँगनवाड़ी वर्कर्स को संगठित करने में मदद की; कृषि कानूनों और श्रम कोडस् के खिलाफ राज्य में चल रहे संघर्षों में सक्रिय थे, कर्नाटक में सामाजिक उत्पीड़न के खिलाफ संघर्ष में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई और दलित हकुगला समिति (दलित अधिकार आंदोलन) का एक हिस्सा था। वह राज्य में 'देवदासी' महिलाओं के आंदोलन को संगठित करने में सक्रिय रूप से शामिल रहे।

सीटू ने शोक संतप्त परिवार और साथियों के प्रति अपनी हार्दिक संवेदना व्यक्त की।

कामरेड नरेंद्र कुमार

सीटू ने उत्तर प्रदेष सीटू के राज्य उपाध्यक्ष कामरेड नरेंद्र कुमार को श्रद्धांजलि दी। वह 75 वर्ष के थे।

कामरेड नरेंद्र कुमार यूपी के बिजनौर जिले के स्योहारा चीनी मिल में कामगार थे; चीनी मिल मजदूरों के संगठन में सक्रिय हुए और कई संघर्षों का नेतष्त्व किया। वह यूपी में षुगर वर्कर्स फेडरेषन (सीटू) के महासचिव थे।

सीटू ने गहरा शोक और षोक संतप्त परिवार के सदस्यों और साथियों के लिए अपनी हार्दिक संवेदना व्यक्त की।

कामरेड संदीप घटक

26 अक्टूबर को 52 वर्श की आयु में वाराणसी के एक अस्पताल में कोविद–19 महामारी के कारण सीटू वाराणसी जिला कमेटी के संयुक्त सचिव, कॉमरेड संदीप घटक के निधन पर सीटू स्तब्ध और दुःखी है।

कॉमरेड संदीप अपने कॉलेज के दिनों में वाराणसी हिंदू विष्वविद्यालय में एसएफआई के पदाधिकारी थे। बाद में, एक चिकित्सा प्रतिनिधि के रूप में काम करते हुए वे एफएमआरएआई की कौंसिल आंदोलन के अखिल भारतीय कार्यकर्ता थे और उत्तर प्रदेष में इसकी वाराणसी इकाई के सचिव भी थे। वह सीपीआई(एम) के सदस्य थे और सीपीआई(एम) की पष्चिम बंगाल पार्टी के दैनिक समाचार पत्र 'गणषक्ति' के रिपोर्टर भी थे।

वे रक्तदान षिविर, बाढ़ राहत कार्य और प्रवासी मजदूरों के बीच राहत कार्य आयोजित करने वाले सामाजिक कार्यों में बहुत सक्रिय थे। वह वाराणसी में औद्योगिक क्षेत्र के मजदूरों और रेलवे कारखाना मजदूरों के आंदोलन के बीच सक्रिय थे।

उन्होंने अपने पीछे अपनी पत्नी, जो एक मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव है, और उनकी एक बेटी को छोड़ा है। उनकी इच्छा के अनुसार, उनके परिवार ने चिकित्सा अध्ययन और अनुसंधान के लिए अस्पताल को उनका षरीर दान कर दिया।

सीटू ने कॉमरेड संदीप के साथियों और उनके परिवार के सदस्यों के प्रति अपनी संवेदना व्यक्त की।

सम्पादकीय

26 नवम्बर की आम हड़ताल की महत्ता

सीटू मजदूर

सीआईटीयू का मुखपत्र

नवम्बर 2020

सम्पादक मण्डल

सम्पादक

के. हेमलता

कार्यकारी सम्पादक

जे. एस. मजुमदार

सदस्य

तपन सेन,

एम. एल. मलकोटिया,

कश्मीर सिंह ठाकुर,

पुष्पेन्द्र त्यागी,

एच.एस. राजपूत

अंदर के पृष्ठों पर

26 नवम्बर 2020 देशव्यापी आम हड़ताल –तपन सेन 5

अब जो परिस्थिति है –के. हेमलता 9

सीटू वर्किंग कमेटी मीटिंग की रिपोर्ट 13

कोविद–19 महामारी – आर करुमलायन 16

कोविद–19 पर सीटू वर्किंग कमेटी मीटिंग 17

शाह आलम खान 18

बोलिवियन की नयी संसद में महिला सांसद 21

आत्मनिर्भर भारत के लिए संघर्ष – जे.एस. मजुमदार 23

26 नवम्बर 2020 को मजदूरों की देशव्यापी आम हड़ताल एक नया अनुभव होगा क्योंकि यह एकदम से नये हालात में होने जा रही है। कोविद–19 महामारी के स्वास्थ्य सम्बन्धी प्रतिबन्धों; और आपदा प्रबंधन कानून एवं धारा 144 के तहत बड़े पैमाने पर लामबन्दी एवं विरोध प्रदर्शनों पर सरकारी प्रतिबन्धों के कारण ये नए हालात पैदा हुए हैं; महज इतना भर ही एक असाधारण स्थिति नहीं है। यह विरोध करने के अधिकार और नागरिक स्वतंत्रता के अधिकार को कुचलना भी है। साथ ही साथ लोकतांत्रिक परम्पराओं और संस्थानों को दबोचकर छीन लेना; सत्ता का अतिकेंद्रीयकरण करते हुए तानाशाही शासन थोपना भी है।

कोविद–19 के कारण बनी इस स्थिति का फायदा सत्तारूढ़ शासकों द्वारा उठाया जा रहा है। नीति आयोग ने इसे शासकों लिए 'अभी नहीं तो कभी नहीं' के तौर पर बताया है। जनविरोधी और राष्ट्रविरोधी अध्यादेशों की श्रृंखला जारी की गयी है, कार्यकारी आदेश पारित किए गये हैं और विपक्ष मुक्त संसद में कानूनों को पारित किया गया है जिनमें मजदूर–विरोधी तीन लेबर कोडस् और किसान–विरोधी तीन कृषि कानून शामिल हैं।

26 नवंबर को मजदूरों की यह आम हड़ताल ट्रेड यूनियन आंदोलन और किसानों के आंदोलन की संयुक्त कार्रवाईयों के सिलसिले की परिणति है; जो विरोध के तौर तरीकों जैसे कि संस्थानिक – बाहर निकलने– से कदम–दर–कदम आगे बढ़ते हुए – बड़े पैमाने पर लामबन्दी; और स्थानीय से लेकर उच्च स्तर एवं राष्ट्रीय स्तर पर आयोजित की गयीं हैं। 21 अप्रैल, 3 जुलाई, 16–17 जुलाई, 9 अगस्त, 5 सितंबर, 25 सितंबर इत्यादि इन सभी दिनों में देश भर के लाखों मजदूरों–किसानों–खेत मजदूरों और अन्य तबकों के साथ समन्वय करते हुए विरोध प्रदर्शन की कार्रवाईयां की गयी।

26 नवंबर की आम हड़ताल केंद्र और राज्यों में भाजपानीत सरकारों के नए हमलों के खिलाफ चल रहे प्रतिरोध आंदोलन के हिस्से के तौर पर अगले चरण में इसे उच्च स्तर पर उठाने के एक और चरण की परिणति है।

गौरतलब है कि मजदूरों की 26 नवंबर की आम हड़ताल केवल मजदूरों की 12 सूत्रीय माँगों को लेकर ही नहीं है; बल्कि इस तानाशाही शासन को चुनौती देने के लिए भी है; और लोकतंत्र की रक्षा में, नागरिक स्वतंत्रता और असहमति जाहिर करने के अधिकार; के लिए भी है।

26 नवम्बर को मजदूरों की आम हड़ताल

हड़ताल नोटिस पर केन्द्रीय ट्रेड यूनियनें और फेडरेशनें

2 नवंबर 2020

केंद्रीय ट्रेड यूनियनों और स्वतंत्र क्षेत्रीय फेडरेशनों/एसोसिशनों के संयुक्त मंच के सभी घटक यूनियनों/फेडरेशनों का संयुक्त परिपत्र

प्रिय साथियों और दोस्तों,

हम 26 नवंबर 2020 को देषव्यापी आम हड़ताल की सक्रिय तैयारी के अभियान के दौर में हैं, जिसका आह्वान, 2 अक्टूबर 2020 को केन्द्रीय ट्रेड यूनियनों और स्वतंत्र क्षेत्रीय फेडरेषन/एसोसिएशनों के संयुक्त मंच की पहल पर ऑन लाइन आयोजित मजदूरों के राश्ट्रीय सम्मेलन ने किया है।

अधिकांश राज्यों में पहले ही संयुक्त सम्मेलन आयोजित किए जा चुके हैं। कई राज्यों में जिला और उद्योग स्तरों पर संयुक्त सम्मेलन भी आयोजित किए गए हैं। केंद्र और कई राज्यों की सरकारों की मजदूर विरोधी, जनविरोधी और देष विरोधी नीतियों के खिलाफ एक साथ अभियान चलाया जा रहा है। जिसमें 26 नवंबर 2020 की आम हड़ताल के लिए संयुक्त घोशणा में दोहराए गए कामकाजी जनता की मांगों का चार्टर मुख्य केन्द्र बिन्दु है।

इन तैयारियों में 10 नवंबर 2020 तक या उससे पहले सभी यूनियनों द्वारा आम हड़ताल के लिए संबंधित प्रबंधन/अधिकारियों को बिना किसी चूक के नोटिस सौंपे जाने चाहिए।

संयुक्त मंच की सभी यूनियनों/फेडरेशनों/एसोसिएशनों से अनुरोध है कि कृपया इस आवश्यकता पर ध्यान दें और तदनुसार पहल करें।

हमें 26 नवंबर 2020 को पूरे देश में बड़े पैमाने पर देशव्यापी हड़ताली कार्रवाई के लिए एकजुट होना चाहिए।

अभिवादन के साथ,

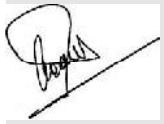

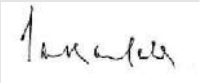

इंटक **एटक** **एचएमएस** **सीटू** **एआईयूटीयूसी**

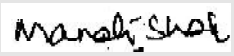

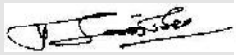

टीयूसीसी **सेवा** **एआइएसीसीटीयू** **एलपीएफ** **यूटीयूसी**

तथा स्वतंत्र क्षेत्रीय फेडरेशनें/एसोसिएशनें

26 नवंबर 2020 की देशव्यापी आम हड़ताल
संदर्भ और मुद्दा

तपन सेन

केंद्रीय ट्रेड यूनियन और फेडरेशनों के संयुक्त मंच ने मोदी सरकार की जन–विरोधी, मजदूर–विरोधी, राष्ट्र–विरोधी विनाशकारी नीतियों के खिलाफ संयुक्त पहल करते हुए 26 नवंबर 2020 को देशव्यापी आम हड़ताल का जो आह्वान दिया है हम उसी ओर बढ़ रहे है।

ये आम हड़ताल निश्चय ही, 1991 से नव–उदारवादी नीति व्यवस्था के खिलाफ हुई 19 आम हड़तालों से बड़ी और व्यापक होने वाली है, जैसा कि लगभग सभी केंद्रीय ट्रेड यूनियन व क्षेत्रीय स्वतंत्र फेडरेशनों द्वारा देशव्यापी व क्षेत्रव्यापी स्तर पर चल रहे संयुक्त और स्वतंत्र तैयारी अभियानों की व्यापकता न सिर्फ सभी उद्योगों व सेवाओं, संगठित व असंगठित दोनो क्षेत्रों में है। बल्कि इसे मजदूरों और कर्मचारियों के साथ ही साथ मेहनतकश जनता के हर तबके खासकर किसान व खेत मजदूर, जो कि पहले से ही जुझारु विरोध व कार्रवाहिया कर रहे है, का भी समर्थन मिल रहा है। वे भी कई लाखों की संख्या में केन्द्र सरकार की विनाशकारी और बर्बर नीति व्यवस्था के खिलाफ, हड़ताली मजदूरों और कर्मचारियों के साथ, सड़कों पर नारे लगाते दिखेंगे।

लेकिन, हमारा काम 26 नवंबर 2020 की आम हड़ताल की सफलता के साथ समाप्त नहीं होता है। यह बर्बर नीति शासन का पूरा ढाँचा पूरी तरह से देश को लूटने के साथ–साथ पूरी मेहनतकश जनता को लूटने वाला है। वर्तमान सरकार द्वारा, सभ्य समाज में मानव अस्तित्व के आवश्यक बुनियादी हकों को भी छीन कर, केवल अपने देशी–विदेशी दोनों ही कॉरपोरेट–भूस्वामी आकाओं की सेवा के लिए ही तैयार किया गया है। और यह कोविद–19 महामारी और लॉकडाउन का लाभ उठाते हुए, विशेष रूप से जनता के सामूहिक असंतोष, विरोध और आंदोलन के अधिकार पर किया जा रहा है। हमारा यह काम इस नीति के खिलाफ और अधिक व्यापक एवं जुझारु जन कार्यवाहियों को अवज्ञा और प्रतिरोध के उंचे स्तर तक ले जाने की शुरुआत है।

2 अक्टूबर 2020 को मजदूरों के राष्ट्रीय कन्वेंशन ने 26 नवंबर 2020 पर चर्चा करते हुए जोर देते हुए कहा कि ''हम बता देना चाहते है कि यह एक दिन की आम हड़ताल आगे आने वाले अधिक दृढ़, अधिक तेज और लम्बे संघर्षों की तैयारी है''। इसका मतलब है कि 26 नवंबर की हड़ताल को लगातार भावी बड़ी कार्यवाहियों का युद्धघोष बनना होगा। इसलिए हड़ताल के लिए चल रहे तैयारी अभियानों को संकटग्रस्त इस नवउदारवादी पूँजीवादी व्यवस्था के सत्तासीन सरकारी टट्टूओं द्वारा मजदूर वर्ग के समक्ष खड़ी की गई चुनौतियों के खिलाफ लम्बे संघर्षों व संयुक्त कार्यवाहियों की निरंतरता को बनाए रखने के लक्ष्य के साथ और तेज करना होगा।

आज की चुनौतियां

जैसा कि 7 अक्टूबर 2020 को हुई सीटू सचिवमंडल की बैठक में कहा गया *''आज हम शासक वर्गों द्वारा उनके वर्गीय हितों की सेवा के लिए बनाई गई एक 'असामान्य स्थिति' में हैं। अर्थव्यवस्था, शासन और प्रशासन व समाज पर अपने आपराधिक तंत्र को वैध बनाने के लिए इसे ''नव–सामान्य'' बताया जा रहा है। मोदीनीत भाजपा सरकार लॉकडाउन का उपयोग और आपदा प्रबंधन अधिनियम के तहत लगाए गए प्रतिबंधों का उपयोग कर सभी संस्थानों, प्रक्रियाओं और मानदंडों पर धावा बोल रही है और जनता पर हमला कर रही है। असल में महामारी का सामना*

करने और जनता को सुरक्षा और सस्ता उपचार सुनिश्चित करने के लिए कुछ भी नहीं किया गया है। इसके बजाय, इस संकट में भी आम जनता की कीमत पर निजी कॉरपोरेट स्वास्थ्य सेवाओं को अच्छा मुनाफा बनाने की अनुमति दी जा रही है।''

19–20 अक्टूबर 2020 को हुई सीटू वर्किंग कमिटी की बैठक ने इशारा किया *''आमतौर पर जनता के बीच यह प्रचार किया जा रहा है कि यह असामान्य परिस्थिति केवल तभी तक है जब तक कि महामारी की परिस्थिति रहेगी। यह पूरी तरह गलत है। बल्कि कोविद–19 महामारी व उसके कारण हुए लॉकडाउन का इस्तेमाल शासक वर्ग द्वारा पूँजीपति वर्ग के हितों की सेवा करने के लिए आर्थिक, राजनीतिक व्यवस्था और पूरे समाज को फासीवादी इरादे के साथ तानाशाह शासन की ओर ले जाने के लिए हो रहा है।''*

भाजपा सरकार द्वारा शासन व्यवस्था का इस तरह से आक्रामक तानाशाह केंद्रीकरण, संविधान को पूरी तरह से कमजोर करना और शासन प्रक्रिया में बुनियादी लोकतांत्रिक मूल्यों को कम करना, सामाजिक एकता की जड़ों पर हमला समाज में एक प्रकार की अराजकता और अपराधीकरण को बढ़ावा देने में किया जा रहा है।

इस प्रकार मोदीनीत भाजपा सरकार अपने नवउदारवादी एजेंडे को पूरा करने की जल्दी में है – मजदूर वर्ग के कड़े संघर्षों से हासिल अधिकारों व हितलाभों को रद्द करना, सार्वजनिक क्षेत्र सहित सार्वजनिक सेवाओं का पूर्ण निजीकरण व कृषि अर्थव्यवस्था को पूरी तरह से बर्बाद कर रही है। देश में बड़े घरेलू और विदेशी कॉरपोरेट एवं व्यापारिक घरानों, के मुनाफों के लिए छोटे किसानों के वर्चस्व वाली कृषि को बदल रही है। सरकारी खरीद को आवश्यक रूप से समाप्त करके सार्वजनिक वितरण प्रणाली को भी समाप्त करने के इरादे से आवश्यक वस्तु अधिनियम में भी संशोधन किया गया है। पूरा षड्यंत्र ही फासीवादी इरादे के साथ अपनी नीतियों के सभी प्रकार के विरोध दमन करने और कॉरपोरेट हितों की रक्षा करने के लिए तानाशाही शासन को लागू करने का है। मोदी सरकार अपने सभी विनाशकारी कुकर्मों को पूरा करने के लिए ''अभी या कभी नहीं'' के परिलक्षण पर चल रही है।

समाज के सबसे शोषित वर्गों, दलितों, अल्पसंख्यकों पर क्रूर हमले और अत्याचारों का कहर, सरकार, प्रशासन और कभी–कभी न्यायपालिका के आभासीय प्रायोजन के साथ भी बरपाया जा रहा है। विशेष रूप से सबसे शोषित दलित वर्ग की महिलाओं पर हमले और हिंसा खतरनाक रूप से बढ़ गई है। एक स्पष्ट तानाशाहीपूर्ण, फासीवादी और बर्बर इरादे के साथ पूरे समाज पर भय और आतंक का माहौल बनाने की कोशिश की जा रही है। यह आरएसएस के साम्प्रदायिक ध्रुवीकरण और 'हिंदुत्व' की विचारधारा के एजेंडे को आगे ले जाने के लिए असहमति का दमन करने और हर प्रतिरोध को कमजोर करने के लिए लॉकडाउन की शर्तों का इस्तेमाल किया जा रहा है। यह सब कॉरपोरेट–जमीदार वर्गों को लाभ पहुंचाने के लिए किया जा रहा है।

विपक्ष की अनुपस्थिति में और बिना किसी चर्चा के संसद द्वारा पारित किए जाने वाले सभी लेबर कोडस् का असल मकसद, मजदूरों के सभी अधिकारों एवं संरक्षणों को खत्म करना और मेहनतकश जनता पर दासता की स्थिति थोपना ही है। और यह कदम मोदी शासन द्वारा अर्थव्यवस्था, राजनीतिक प्रणाली और सामाजिक व्यवस्था को निरंकुश व्यवस्था बनाने की विनाशकारी परियोजना का अभिन्न अंग है। श्रम संहिता के माध्यम से श्रम अधिकारों पर अंकुश लगाने का यह कदम लोकतांत्रिक अधिकारों पर असहमति, विरोध और सामूहिक रूप से विरोध करने के अधिकार पर भी हमला है जैसा कि सामाजिक कार्यकर्ताओं, बुद्धिजीवियों और सभी सीएए आंदोलनकारियों की प्रतिशोधी गिरफ्तारी और उप पर हमलों में देखने को आया है। संसद के मानसून

सत्र के दौरान कृषि और श्रम संहिता पर कानून पारित करते समय संसदीय मानदंडों और प्रक्रियाओं को पैरो तले रौंदा गया और सभी संवैधानिक प्रावधानों और प्रक्रियाओं की नाफरमानी की गई है। ये कदम एक स्पष्ट फासीवादी इरादे के साथ पूरी लोकतांत्रिक व्यवस्था को रौंदने के निर्णायक कदम के अहम हिस्सा हैं।

इसलिए साथियों, हमारे सामने चुनौती केवल निजीकरण या श्रम अधिकारों पर हमलों या जमींदार–कॉरपोरेट–विदेशी व्यापारियों की सांठगांठ के पक्ष में कृषि अर्थव्यवस्था का मुकम्मल परिवर्तन ही नहीं है, हमारे सामने चुनौती इससे भी बहुत बड़ी है। असल में यह एक पूर्ण अधिकृत तानाशाह शासन की स्थापना और लोकतांत्रिक व्यवस्था को रौंदने की परियोजना से निपटने की है, जो देशी–विदेशी निजी कॉरपोरेट मालिकों द्वारा राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था और संसाधनों की खुली बेरोक–टोक लूट की अनुमति देने के लिए है। इसलिए हमारा संघर्ष, हमारे देश की अर्थव्यवस्था को गिरवी रखने, देश के संसाधनों को एक थाल पर परोस नीलाम करने के खिलाफ है, गैर–औद्योगिकरण के राष्ट्रविरोधी षडयंत्र को पराजित करना, जनता की एकता को विघटन की जहरीली साजिशों से बचाना है, वास्तव में यह संपूर्ण भारत एवं उसकी संप्रभुता का पूरी ताकत से बचाव भी करना है। मेहनतकश जनता, मोदी शासन के इस अत्याचारी व्यापक खेल की योजना से अपना और अपने अधिकारों का बचाव केवल आमने–सामने की लड़ाई कर के ही कर सकती है।

यहाँ मेहनतकश जनता के एकजुट संघर्ष को अवज्ञा और प्रतिरोध के स्तर तक ले जाने का महत्व और जल्दी पता चलती है। हमारे अभियान, आंदोलन और कार्रवाहियों को न केवल जनता के जीवन और आजीविका पर नीति व्यवस्था के दुखद प्रभाव से निपटना चाहिए, बल्कि उन्हें नीति व्यवस्था से भी जोड़ना चाहिए और ऐसी राजनीति का पर्दाफाश करना चाहिए जो इस तरह की विनाशकारी नीतियों को बढ़ावा देती है। और साथ ही साथ हमें जनता के सामने ढ़ीठ जन–विरोधी राजनीतिक–आर्थिक व्यवस्था का जन–समर्थक विकल्प पेश करना होगा। ट्रेड यूनियनों के संयुक्त मंच की 12 सूत्रीय मांगें और 2019 में संयुक्त मंच द्वारा उसके आधार पर तैयार किए गए जनता के चार्टर जो जन–समर्थक लोकतांत्रिक विकल्प पर आधारित है, उसे प्रभावी और ठोस तरीके से मेहनतकश जनता तक पहुंचाने की जरूरत है।

इसलिए, हमारे अधिकारों और हितलाभों का बचाव करने के लिए संघर्ष, हमारे कार्यस्थलों और रोजगार आदि के बचाव के लिए संघर्ष को अर्थव्यवस्था, राजनीतिक प्रणाली और तानाशाही और विभाजनकारी दिशा की ओर समाजिक प्रबंधन के व्यापक संरचनात्मक परिवर्तन के खिलाफ संघर्ष से अलग नहीं किया जा सकता है। क्योंकि शासन के कुल संरचनात्मक परिवर्तन के लिए मोदी सरकार की इस व्यापक परियोजना से हमारे अधिकारों और कार्यस्थलों पर हमले हो रहे हैं और हमें उसकी जड़ों पर ही चोट करनी होगी।

मजदूर वर्ग का सामूहिक हस्तक्षेप इस तरह का उद्देश्य रखता है कि मोदी शासन की इच्छा के अनुसार कामों को न होने दें। प्रतिरोध को क्षेत्रीय स्तर पर और राष्ट्रीय स्तर पर इसकी हर संदिग्ध कार्यवाही के प्रत्येक चरण में खड़ा करने की आवश्यकता है। और इसके लिए अर्थव्यवस्था व समाज की सभी उत्पादक ताकतों को एकजुट संघर्षों के एकजुट मंच की आवश्यकता है। देश भर में किसानों और खेत मजदूरों के बढ़ते संघर्षों से इस दिशा के पूरे वातावरण में सकारात्मक बदलाव आया है। मजदूर वर्ग के आंदोलन को किसान और खेत मजदूर संगठनों के साथ संयुक्त संघर्ष का निर्माण निरंतर तरीके से करना है और संयुक्त मोर्चों को विकसित करना है और उनके साथ जमीनी स्तर पर समन्वय स्थापित करना है। सीटू को असफल हुए बिना इस दिशा में विशेष पहल करनी होगी। हम पहले से ही एआईकेएस और एआईएडब्लयूयू के साथ बड़ी संयुक्त आंदोलनकारी गतिविधियों का

अभ्यास कर रहे हैं और इसने समाज के दो मुख्य उत्पादक शक्तियों के बीच आपसी सहयोग और एकजुटता की प्रक्रिया में अन्य ट्रेड यूनियनों और किसान संगठनों को आकर्षित करना शुरू कर दिया है। जिससे मजदूरों और किसानों का जन–आंदोलन के एकजुट मंच की नींव को विकसित कर रहे है। इस प्रक्रिया को और अधिक व्यापक एवं समेकित किया जाना है।

हम पहले से ही 26 नवंबर 2020 की आम हड़ताल के लिए हमारे तैयारी अभियानों में लगे हुए हैं। बाकी बचे हुए दिनों के दौरान इसे मजबूत करने की जरुरत है। हम कुछ भी इत्तेफाक़ पर नहीं छोड़ सकते। हम समय को हाथ से निकलने और बर्बाद नहीं होने दे सकते। देश और जनता के दुश्मनों के सभी दुष्ट और हानिकारक मंसूबों को हराने की अजेय भावना हमारी सभी गतिविधियों का प्रेरणास्त्रोत होनी चाहिए।

हमारा दुश्मन वर्ग हमारे अधिकारों और पात्रता को दबाने और कामकाजी जनता पर गुलामी की शर्तों को थोपने के लिए 'अभी या कभी नहीं' के कुत्सित इरादों के साथ काम कर रहा है। मजदूर वर्ग के लिए, यह 'अब' अपने आक्रामक रूप का प्रदर्शन करते हुए और हर कदम पर विरोध खड़ा करते हुए, दासता को थोपने के विनाशकारी मंसूबे को कभी अनुमति नहीं देना है। हम ऐसा कर सकते हैं, निश्चित रूप से हम ऐसा कर सकते हैं। अभी मजदूरों को प्राप्त अधिकारों में से कोई भी स्वतः नहीं मिला है। आठ घंटे काम करने का अधिकार, हड़ताल का अधिकार सहित संगठित होने का अधिकार, सामूहिक सौदेबाजी और शिकायत निवारण का अधिकार, इन अधिकारों के अलावा, मजदूर वर्ग ने पहले जुझारु संघर्षों के माध्यम से, जबरदस्त बलिदानों के दौर से गुजर कर, और उस प्रक्रिया के माध्यम से समाज और शासन को मजदूर वर्ग के उन अधिकारों को मान्यता देने के लिए मजबूर होना पड़ा था। यह जन्म से ही मजदूर वर्ग के आंदोलन का इतिहास है।

जब कई राज्यों में अध्यादेशों के माध्यम से इन अधिकारों को समाप्त करने के लिए निशाना बनाया उन्हीं को श्रम संहिता के जरिये छीना जा रहा है, तो हम इसे, अत्याचारी मंसूबों के खिलाफ अवज्ञा व प्रतिरोध के लिए 'अधिकारों को छीनने की साजिश' के तौर पर लेते हैं। पहले से ही भारतीय मजदूर वर्ग के आंदोलन के रंगमंच में ऐसी अवज्ञा शुरू हो गई है। कोयला मजदूरों की तीन दिन की हड़ताल, बीपीसीएल के मजदूरों की दो दिन की हड़ताल, भाजपा शासित राज्यों में सीमेंट मजदूरों का संघर्ष और आखिरी लेकिन इकलौता नहीं, निजीकरण के खिलाफ यूपी के बिजली कर्मचारियों द्वारा किया गया वीरतापूर्ण संघर्ष मजदूर वर्ग द्वारा ऐसे एकजुट अवज्ञा संघर्षों का प्रमाण है।

और हम अकेले नहीं हैं। मजदूर वर्ग लगभग दुनिया भर में, सम्बन्धित शासक वर्ग द्वारा अपने अधिकारों पर इसी तरह के हमलों के खिलाफ संघर्षों के रास्ते पर हैं। इंडोनेशिया के मजदूरों द्वारा 6–8 अक्टूबर 2020 को तीन दिवसीय बड़ी व्यापक हड़ताली कार्रवाई नवीनतम उदाहरण है।

हमें लड़ना है, हम लड़ सकते हैं और हमारी जीत निश्चित है क्योंकि अंततः मजदूर–विरोधी, जन–विरोधी और राष्ट्र–विरोधी नीतियों को मुकम्मल रुप से परास्त ही होना है।

19–20 अक्टूबर 2020 को सम्पन्न हुई सीटू वर्किंग कमेटी की रिपोर्ट के निष्कर्ष वाक्य के साथ मैं अपनी बात का समापन करता हूँ, *''हमें 26 नवंबर की आम हड़ताल और आने वाले सभी जुझारु संघर्षों व हड़तालों की तैयारियां इस समझ के साथ शुरु करनी होगी कि अगर यह शासक वर्ग के लिए 'अभी या कभी नहीं' है तो 'अब' हमारे लिए भी ये यही है।''*

''हम ही जीतेंगे''

'अब' जो परिस्थिति है

के. हेमलता

मौजूदा परिस्थिति मजदूरों के लिए सामान्य नहीं है। यह निश्चित ही असामान्य है। लेकिन क्या यह 'नई' है? क्या यह 'नई सामान्य' परिस्थिति है? क्या यह 'नई' है? आखिर यह किस तरह की परिथिति है?

वर्तमान परिस्थिति का सामना करने के लिए इसे समझना आवश्यक है। 24 मार्च 2020 की शाम अचानक देशव्यापी लॉकडाउन की घोषणा से परिस्थिति नाटकीय रुप से बदल दी गई। चार घंटे के भीतर लॉकडाउन लागू हो गया।

तब तक नियमित वेतन पाने वाले करोड़ों मजदूरों को लग रहा था कि उनका जीवन कमावेश सुरक्षित है। उनका वेतन ज्यादा भले ही न रहा हो उनमें से ज्यादातर को वह न्यूनतम वेतन भी नहीं मिल रहा हो जिसकी माँग ट्रेड यूनियनों द्वारा कई बरस पूर्व 2015 में की गई थी। उनमें से अधिकतर का वेतन 12000/15000 रुपये प्रतिमाह था। लेकिन इतने कम वेतन में भी जो सबसे आश्वस्त करने वाली बात थी वह यह थी कि वेतन नियमित था; वे अपना खर्चा नियोजित कर अपने बजट को संतुलित कर सकते थे; उन्हें किसी के सामने मांगने या हाथ फैलाने की जरुरत नहीं थी। वे सम्मान के साथ रह रहे थे।

यह सब अचानक बदल गया। करोडों लोग जब सुबह उठे तो उन्होने पाया कि नियोक्ताओं को उनकी सेवाओं की और जरुरत नहीं थी। वे जो प्रदान करते थे समाज अब उसे उपयोग करने में सक्षम नहीं था। उन्होने अपना रोज़गार और आय का एकमात्र स्रोत खो दिया था। अचानक ही, तब तक सम्मान से जीते आये इन लोगों ने अपने आपको असहाय व कमजोर पाया। उन्होने पाया, कि वे अपने बच्चों के स्कूल की फीस नहीं दे सकते है; किराया नहीं दे सकते है; नियमित भोजन नहीं कर सकते हैं। बिना किसी के आगे हाथ फैलाये अपने साधनों के साथ सम्मान के साथ जीने पर जो गर्व उन्हें था वह बिखर गया। अब कितनों को अस्तित्व बचाये रखने के लिए मदद के हेतु दूसरों पर निर्भर होने को मजबूर होना पड़ा है।

उनका जीवन उलट–पलट हो गया

प्रधानमंत्री ने कहा कि कोविद–19 को थामने के लिए यह सब करना आवश्यक था। इसे 21 दिनों, महाभारत की 18 दिन की लड़ाई से तीन दिन ज्यादा का युद्ध कहा गया था। ऐसा लगता है कि कोरोना वायरस कौरवों से ज्यादा शक्ति शाली है और छप्पन इंच निश्चित ही अर्जुन के बराबर होने का दावा नहीं कर सकता जिसके सारथी और कोई नहीं स्वंय कृष्ण थे। मास्क पहनने, हाथ धोने, सामाजिक दूरी आदि के उपदेश की रस्म अदायगी के बाद ताली–थाली, घंटे–घडियाल बजाना, बत्तियां जलाना–बुझाना तो 'गो कोरोना गो' के नारे लगाने के साथ ही हवन, पूजा इत्यादि सभी को इस युद्ध में शक्ति शाली हथियार बताया गया था।

उन्होने उस पर विश्वास किया। कोरोना के विरुद्ध इस युद्ध में वे अपनी शक्ति भर योगदान करना चाहते थे जैसे 4 साल पूर्व उन्होनें नोटबंदी के दौरन अपने रोज़गार और आमदनी खोकर किया था। उस समय मोदी ने कहा था, कि काले धन, भ्रष्टाचार, आंतकवाद से लड़ने के लिए ऐसा करना जरुरी हैं। इसी प्रकार उन्होने मोदी व भाजपा के लिए वोट किया क्योंकि उन्हें लगा था कि वे देश को आस्थिर करने पर लगी तथाकथित 'राष्ट्र विरोधी' ताकतों के विरुद्ध लड़ाई में अपनी देश भक्ति की जिम्मेदारी निभा रहे हैं।

अब 21 नहीं, 210 दिन से भी ज्यादा गुजर चुके हैं। लेकिन कोविद–19 पर जीत कहीं दिखाई नहीं दे रही। बल्कि, संक्रमितों की कुल संख्या व मौतों के हिसाब से भारत अब अमेरिका के बाद दूसरे स्थान पर पहुँच गया है। मजदूर व आम लोग चिन्तित हैं कि सामान्य स्थिति कब लौटेगी।

अधिकतर मजदूरों व आम लोगों को उम्मीद थी कि संकट में सरकार उनकी मदद करेगी। उन्हें उम्मीद थी कि कम से कम सरकार के अपने आदेश कि रोज़गार नहीं छिनेगा, वेतन में कटौती नहीं होनी चाहिये को लागू किया जायेगा; कि सरकार कम से कम यह सुनिश्चत करेगी कि प्रवासी मजदूर सुरक्षित अपने गांव में पहुँच जायें; कि वह सुनिश्चित करेगी कि वे भूखे नहीं मरेंगें।

लेकिन उन्होंने पाया कि ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। बल्कि सरकार ने 53 दिन में अपना आदेश वापिस ले लिया जब उसे अदालत में चुनौती दी गई। 'आत्मनिर्भर' का पैकेट भी मजदूरों या आम जन के लिए नहीं था। इसमें जो था वह यह था कि निवेश को प्रोत्साहित करने के लिए कॉरपोरेट को छूट दी जायेगी जिससे रोजगार बढ़ेगा जिससे जनता व अर्थव्यवस्था को मदद मिलेगी। श्रम कानूनों का संहिताकरण, निजीकरण, कषषि विधयेकों आदि के पुराने फैसलों को भी 'राहत पैकेट' का अंग बना दिया गया।

न केवल सरकार की ओर से कोई मदद नहीं आयी बल्कि मजदूरों को यह देखकर और भी हताशा हुई कि मोदी सरकार एक–एक कर उस थोड़ी सी सुरक्षा को और थोड़े से अधिकारों को जो उनके पास के खत्म करने के लिए तेजी से आगे बढ़ रही है। श्रम संहिताओं को संसद में विपक्ष की अनुपस्थिति में बिना चर्चा के परित कर दिया गया। कषषि विधायकों को संसद में मत विभाजन की माँग कर रहे सांसदों को निलंबित कर पारित कर दिया गया। ये सांसद न केवल अपने अधिकार का प्रयोग कर रहे थे वरन वे वहाँ खड़े लोगों को यह दिखना भी चाहते थे; कि किस दल के सांसदों ने विधयेकों का समर्थन किया और कौन से दल के सांसद किसानों के साथ थे। लेकिन, मत विभाजन की माँग करने वाले सांसदों को बाहर धकेल कर विधयेकों को पारित कर दिया गया।

जनता की आवाज़ व असहमति के अधिकार को दबाना

सरकार ने 'कोरोना को थामने' के नाम पर लॉकडाउन थोपने के लिए 'आपदा प्रबंधन एक्ट' का इस्तेमाल किया था। कई स्थानों पर सप्ताहान्त कफ्यू लगाये गये और अनलॉकडाउन होने के बाद भी इन्हें जारी रखा गया। दुकानों व मॉलों के खुल जाने के बाद भी लोगों को जमा होने से रोकने के लिए धारा 144 जारी रही। अपनी माँगो को उठाने के लिए बाहर आये मजदूरों व जनता पर मुकदमें लगा दिये गये। कईयों को जेल में डाला गया। ये उन सबके अलावा थे जिन्हें दलितों पर हमलों का विरोध करने, मानव अधिकारों व नागरिकता के अधिकार पर हमलों का विरोध करने के लिए जेल में डाला गया। आपदा प्रबंधन एक्ट के अतिरिक्त भाजपा सरकार यूएपीए, देशद्रोह एक्ट जैसे कई अन्य कानूनों व एनआइए तथा सीबीआई आदि जैसी एजेंसियों को दबाने के लिए दुरुपयोग कर रही है।

नया क्या है

आज की परिस्थिति में – भाजपा सरकार कोविद–19 महामारी और लॉकडाउन का इस्तेमाल हर तरफ से आम जनता पर हमला करने के लिए कर रही हैं। क्या ऐसी परिस्थिति पूरी तरह से नई है? बेरोजगारी व रोजगार का जाना तो अलग अलग समय पर कम या ज्यादा पहले भी रहें हैं। इसमें इतना कुछ असामान्य नहीं है। अधिकारों और लाभों का लागू होना भी असामान्य नहीं। इसी तरह मौलिक मानव व जनवादी अधिकारों तथा संसदीय नियम–कायदों व संवैधानिक अधिकारों पर हमारे देश में हमले हुए हैं – इंदिरा गांधी के प्रधानमंत्री रहते कांग्रेस शासन में अंदरुनी आपात–काल देश ने देखा है। इसके बीच भी उल्लंघनों व हमलों के कितने ही उदाहरण रहे हैं। ये सब भी पूरी तरह से नये नही हैं।

जो नया और घिनौना है वह यह कि भाजपा सरकार कोविद–19 जैसे स्वास्थ्य व मानवीय संकट तथा लॉकडाउन को, जिसे रोकथाम के लिए थोपा बताया गया, अपने नव उदारवादी एजेंडे को थोपने के लिए इस्तेमाल कर रही है। आर्थिक संकट के बीच मोदी सरकार पूँजीपति वर्ग के मुनाफों को बचाने के लिए इसे अपनी विस्तष्त परियोजना के रुप में लागू कर रही है।

ध्यान देने योग्य महत्वपूर्ण बात यह है कि कोविद–19 के प्रति यह प्रतिक्रिया और आर्थिक संकट विशेष तौर पर अकेले हमारे देश में भाजपा सरकार के लिए ही नहीं हैं। उन्नत पूँजीवादी देषों सहित पूँजीवादी देषों की अधिकांष सरकारों ने भी मजदूरों के कड़े संघर्षों से हासिल मूल अधिकारों और हित लाभों को खासतौर पर उनके यूनियनों में संगठित होने के अधिकारों पर अंकुश लगाकर, आर्थिक संकटों का उसी तरह से जवाब दिया है। स्वास्थ्य पर सार्वजनिक खर्च में भारी कटौती, नवउदारवाद के तहत, जनता को निजी कॉरपोरेट की स्वास्थ्य व्यवस्था की दया पर छोड़ दिया है। दुनिया भर में, महामारी के दौरान, जिन लोगों की मष्त्यु उचित देखभाल की कमी के कारण या तो कोरोना या अन्य बीमारियों के कारण हुई है, वो सभी गरीब हैं।

कोविद–19 महामारी और लॉकडाउन से पहले भी पूँजीवादी संकट मौजूद था। पूँजीपति वर्ग के लिए अपने ठहरे हुए या कम होते मुनाफों को बचाने का एकमात्र उपाय होता है बोझ को मजदूर वर्ग व जनता के अन्य मेहनतकशों के ऊपर डाल देना। मुनाफों को अधिकतम करने और अपनी दौलत को बढ़ाने का एकमात्र रास्ता है जनता की दौलत पर कब्जा – प्राकृतिक संसाधन, तथा सार्वजनिक शिक्षा व स्वस्थ्य समेत सार्वजनिक क्षेत्र पर कब्जा करना, सारी दुनियां में जनता के बीच साख गंवा चुके नवउदारवाद को तेजी से आगे बढ़ाने के अलावा उन्हें दूसरा कोई रास्ता नहीं दिखता।

लेकिन, उन्हें मालूम है कि इसका मजदूरों व जनता द्वारा कड़ा प्रतिरोध होगा। इस प्रतिरोध को अवश्य ही दबाना होता है। कैसे? पहले तो जनता को एकजुट होने और एकजुट होकर लड़ने से रोको। जनता तभी लड़ सकती है जब वह एकजुट हो। इसके लिए आस्था, जाति विभाजन, जेंडर, क्षेत्रीय व जातीय अंतरों को इस्तेमाल, रोजगार छिन जाने, बेरोगारी मूल्य वषद्धि, भूख, गरीबी आदि जैसे वास्तविक मुद्दों से ध्यान हटाने के लिए किया जाता है। उन्हें विश्वास कराया जाता है कि बहुमत को अल्पमत से खतरा है; तथाकथित सवर्ण जातियों को दलितों से खतरा है। उनकी सारी समस्याओं अन्यों या 'दूसरों' के कारण हैं।

अयोध्या में मंदिर बनने, मथुरा में एक और मस्जिद को गिराने, अंतर धार्मिक विवाहों पर नियन्त्रण करने; मनुस्मषति को संविधान मान 'हिन्दू राष्ट्र' स्थापित करने, केवल व्यक्तियों ही नहीं बल्कि पशुओं के लिए भी यह तय करने का कि क्या खाना है क्या नहीं, क्या यह सब करने से रोजगार पैदा हो जायेगा, आमदनी होगी, भूख व कुपोषण खत्म होगा, स्वास्थ्य सुविधाओं में सुधार होगा या कि फौरी परिस्थिति में कोविद–19 से लड़ा जा सकेगा? कि नहीं। लेकिन भाजपा व उसकी केन्द्र व राज्यों की सरकारों के लिए प्राथमिकता नहीं है। इसके साथ–साथ आवाज उठाने की कोशिश करने वालों को डराया, धमकाया जायेगा उन पर हमला किया जायेगा। यानी पीड़ित को निशाना बनाना इन हमलों का विरोध करने वालों को 'राष्ट विरोधी'; 'अंर्बन नक्सल' आदि बताना है; उन्हें गिरफ्तार कर जेल में डाल देना; या उन्हें पाकिस्तान चले जाने को कहना है।

वर्तमान परिस्थिति का निचोड़

देशी–विदेशी कारपोरेटों के हितों को आगे बढ़ाने तथा आर.एस.एस. के 'हिन्दू राष्ट्र' के उद्देश्य को पूरा करना ही नवउदारवाद व साम्प्रदायिकता की इस विस्तष्त परियोजना का निचोड़ है। पूँजीवादी व्यवस्था को जनता के बढ़ते गुस्से से बचाने के लिए मोदी सरकार के तहत यह विस्तष्त परियोजना ही आज नई है। आज साम्प्रदायिक फासीवादी आर.एस.एस. की राजनीतिक शाखा, भाजपा, पूँजीपति वर्ग के हितों की रक्षा में सबसे आगे है।

मौजूदा परिस्थिति, यह दिखती है कि मुनाफे से संचालित पूँजीवादी व्यवस्था को बचाने के लिए पूँजीपति वर्ग किसी भी हद तक जा सकता हैं। एक ऐसी व्यवस्था को जो अभूतपूर्व संसाधनों व दौलत के बावजूद मानवता की बुनियादी समस्याओं का समाधान करने में अक्षम साबित हुई है। मौजूदा व्यवस्था में कोई विकल्प न होने की स्थिति में, कोविद–19 व लॉकडाउन उसके लिए स्वर्णिम अवसर की तरह आये, मुनाफों को अधिकतम करने और दौलत बटोरने के लिए 'भगवान का कारनामा'। उन्हें लिए यह अभी नहीं तो कभी नहीं है। उनकी बदहवाशी का स्तर ऐसा है।

नवउदारवादी के ढ़ोलची मौजूदा परिस्थिति को एक 'नव सामान्य' (न्यू नार्मल) के रुप में चित्रित करने की कोशिश कर रहे हैं। वे ऐसा दिखाना चाहते है कि अब आगे मजदूरों की स्थिति 19वीं सदी के गुलामों के जैसी होगी जो, सामान्य होगी; कारपोरेट कषषि व्यापार द्वारा हमारे किसानों का नियन्त्रण अब से 'सामान्य' होगा; हमारे देश का आत्मनिर्भरता व सम्प्रभुता को खोना अब 'सामान्य' होगा।

बढ़ती अवज्ञा व प्रतिरोध

लेकिन, मजदूर वर्ग, किसान, जनता के प्रगतिशील व देश भक्त तबके मौजूदा परिस्थिति के 'सामान्यीकरण' की ऐसी क्रूर कोशिश को मंजूर नहीं कर सकते हैं। किसी भी परिस्थिति में नहीं। दरअसल, इस परिस्थिति में मुश्किलों व दमन का सामना करते हुए मजदूर वर्ग, किसानों व अन्य मेहनतकशों की अपने अधिकारों व जीविका को बचाने की बढ़ती इच्छा शक्ति व प्रतिबद्धता 'नई' है। लॉकडाउन का दौर कितने ही अभूतपूर्व संघर्षों का दौर था। लॉकडाउन के एक महीने के भीतर ही लाखों लोगों ने जिनमें बड़ी संख्या महिलाओं की थी, अपनी छतों से जोरदार आवाज़ में माँग की कि वह भाषण नहीं राशन दे। सात महीने के लॉकडाउन में कोयला मजदूरों की ऐतिहासिक तीन दिवसीय संयुक्त हड़ताल हुई, तेल मजदूरों की हड़ताल हुई, परियोजना कर्मियों विशेष कर आशा वर्करों की हड़ताल हुई, स्टील मजदूरों तथा बहुत से प्राइवेट उद्योगों के मजदूरों की हड़तालें हुई। इसी दौर में, हमारे देश में धन–संपदा को पैदा करने वाले दो प्रमुख उत्पादकों – मजदूरों व किसानों के बीच एकजुटता व समर्थन उल्लेखनीय रुप से बढ़ा। इस वर्ष 9 अगस्त 23 सितम्बर व 25 सितम्बर को लाखों मजदूरों व किसानों ने सभी तथा एक–दूसरे की माँगो को लेकर प्रदर्शनों में हिस्सेदारी की एक बहुत ही महत्वपूर्ण घटना क्रम में, समूचे मजदूर वर्ग की ओर से ट्रेड यूनियनों के संयुक्त मंच ने, 200 से ज्यादा किसान संगठनों का प्रतिनिधित्व करने वाली आल इंडिया किसान संघर्ष समन्वय समिति द्वारा 26–27 नवम्बर के देशव्यापी विरोध के आहवान को तथा किसान संगठनों ने संयुक्त ट्रेड यूनियन मंच के द्वारा 26 नवम्बर की देशव्यापी आम हड़ताल को समर्थन देने का एलान किया।

कुल मिलाकर यह आज की परिस्थिति है जिसे हमें समझने की आवश्यकता है। शासन वर्गों की बदहवाशी को नोट करने की जरुरत है। इसी के साथ ही मेहनतकशों की एकजुट होकर लड़ने की इच्छा व प्रतिबद्धता को भी अवश्य ही नोट किया जाना चाहिये। बदहवाशी कभी नहीं जीत सकती। लगन अवश्य जीतेगी। एकजुट व प्रतिबद्ध संघर्ष निश्चित ही विजयी होगा। मजदूर वर्ग को इस परिस्थिति को नियन्त्रण में लेना होगा अैर 'अभी नही तो कभी नहीं' के संकल्प के साथ देना होगा। इस लड़ाई की तैयरियां अब शुरु हो जानी चाहिये।

यह परिस्थिति अब मजदूरों, किसानों व अन्य मेहनतकशों से उनके एकजुट कार्रवाईयों, एकजुट अवज्ञा व एकजुट प्रतिरोध की माँग करती हैं। मजदूर वर्ग व उसके नेतष्त्व को अवश्य ही यह ध्यान में रखना है कि इस लड़ाई को तो टाला जा सकता है न ही विंलबित किया जा सकता है और न ही इसे मोड़ा जा सकता है। 26 नवम्बर की आम हड़ताल तथा 26–27 नवम्बर का किसानों का देशव्यापी विरोध शुरुआत है। मजदूर वर्ग द्वारा हड़ताल की तथा किसानों के संघर्ष के साथ एकजुट की तैयारियां शुरु हो चुकी हैं। अब उन्हें तेज किया जाना चाहिये इस समझदारी के साथ कि यह संघर्ष आने वाले दिनों के बड़े संघर्षों की शुरुआत हैं।

सीटू वर्किंग कमेटी की मीटिंग

(19–20 अक्टूबर 2020 को ऑनलाइन आयोजन)

तय किए कार्य

1. सूक्ष्म स्तरीय सीटू समन्वय समितियाँ

नीतिगत मुद्दों और उनके पीछे की राजनीति से संबंधित मुद्दों पर अभियान, आंदोलन और संघर्श करने के लिए निचले/स्थानीय/ग्रामीण स्तर पर सीटू यूनियनों की समन्वय समिति विकसित करने के लिए सभी स्तर पर तत्काल पहल की जानी चाहिए। इससे वर्ग और मेहनतकश जनता की व्यापक एकता विकसित करने में मदद मिलेगी। इस समन्वय समिति को आंदोलन को मजबूत करने के लिए निचले/स्थानीय /ग्रामीण स्तर पर किसान सभा और खेत मजदूर यूनियन के साथ सक्रिय समन्वय विकसित करने में लगन से काम करना चाहिए। इसी तरह के समन्वय को औद्योगिक क्षेत्रों में हमारी यूनियनों और मैत्रीपूर्ण यूनियनों के बीच निर्मित करना है ताकि एकजुट संघर्शों और अभियान में मेहनतकश वर्ग की एकता को व्यापक बनाया जा सके।

2. 26 नवंबर को मजदूरों की आम हड़ताल

ट्रेड यूनियनों के एकजुट मंच द्वारा 26 नवंबर, 2020 को देशव्यापी आम हड़ताल का आयोजन करने का प्रयास किया जाना चाहिए, ताकि मजदूर वर्ग द्वारा जुझारु और प्रभावी, प्रत्यक्ष और एकजुट कार्रवाई की जा सके।

हड़ताल की तैयारी अभियान को गैर–पहुंच तक पहुंचने के आह्वान के अधिक प्रभावी कार्यान्वयन को सुनिश्चित करना चाहिए, निम्न स्तर पर सक्रिय समन्वय समितियों का गठन, जैसा कि नंबर 1 में उल्लेखित है, अगर गंभीरता से प्रयास किया जाता है, तो इस कार्य को अधिक प्रभावी ढंग से निर्वहन करने में मदद मिलेगी।

हड़ताल की तैयारी अभियान का उद्देश्य इस आम हड़ताल के बाद आगे की कार्रवाई के लिए जमीन तैयार होनी चाहिए जिसकी कल्पना ट्रेड यूनियन के संयुक्त मंच द्वारा सर्वसम्मति से कल्पना की गई थी।

3. किसानों के संघर्ष के साथ एकजुटता

अखिल भारतीय किसान संघर्श समन्वय समिति (एआईकेएससीसी) ने क्रूर कर्षि कानूनों के खिलाफ अपने निरंतर संघर्श को जारी रखते हुए 26–27 दिसंबर 2020 को आस–पास के राज्यों में किसानों द्वारा सड़क रोको के माध्यम से बड़े पैमाने पर दिल्ली के घेराव का आयोजन करने और देश भर में उसी दिन जुझारु विरोध प्रदर्शन आयोजित करने का फैसला किया है।

हमें किसानों के संघर्श कार्यक्रमों में सक्रिय सहयोग देना है, 26 नवंबर को सफल आम हड़ताल करते हुए, हमें 26 और 27 नवंबर को सभी संभावित साधनों के साथ किसानों के आंदोलन में भी शामिल होना चाहिए और उनका समर्थन करना चाहिए।

4. निजीकरण विरोधी संघर्ष को व्यापक बनाना

निजीकरण विरोधी संघर्श को सभी आम लोगों के जीवन से जोड़ने के लिए और व्यापक बनाना होगा। विशेश रूप से महत्वपूर्ण और रणनीतिक महत्व के क्षेत्रों, जैसे कि रेलवे, बिजली और स्वास्थ्य सेवा, और प्रभावी मुकाबला तथा प्रतिरोध करने के लिए उपभोक्ताओं सहित सभी तबकों के प्रभावित लोगों को जोड़कर व्यापक मंचों को ट्रेड यूनियन आंदोलन द्वारा विकसित किया जाना है। सीटू राज्य कमेटियों को इस दिशा में सक्रिय पहल करनी होगी।

5. सीटू के स्वर्ण जयंती और प्रथम राष्ट्रीय ट्रेड यूनियन केंद्र के षताब्दी समारोह का समापन

7 नवंबर 2020 को पहले राश्ट्रीय ट्रेड यूनियन केंद्र के गठन के शताब्दी समारोह और सीटू के स्वर्ण जयंती समारोह के समापन पर ऑनलाइन बैठक में हमारी सदस्यता के कम से कम 10 प्रतिशत सदस्यों की भागीदारी को सफल बनाना है। लिंक और तकनीकी व्यवस्था के बारे में और जानकारी जल्द ही भेजी जाएगी।

6. सीटू सदस्यता

16वें सम्मेलन द्वारा तय किए गए सदस्यता लक्ष्य को प्राप्त किया जाना है, 2019 की सभी बकाया सदस्यता अक्टूबर के अंत तक सीटू केंद्र तक पहुंच जानी चाहिए। कैडर विकास गतिविधियों के लिए एक साथ पहल को मजबूत किया जाना चाहिए।

7. डब्ल्यू.एफ.टी.यू. फंड

डब्ल्यू.एफ.टी.यू. के लिए फंड के आह्वान को जल्द से जल्द प्रभावी ढंग से पूरा दिया जाना चाहिए।

सीटू और फेडरेषनों का डब्ल्यू.एफ.टी.यू. फंड में योगदान

वर्ल्ड फेडरेशन ऑफ ट्रेड यूनियन (डब्ल्यू.एफ.टी.यू.), जिससे भारत में सीटू और अन्य वाम नेतष्त्व वाले ट्रेड यूनियन जुड़े हैं, के तत्काल आह्वान के जवाब में सीटू केंद्र, इसकी राज्य इकाइयों व फेडरेशनों ने डब्ल्यू.एफ.टी.यू. फंड में तुरंत, 4 नवंबर 2020 तक, योगदान किया जैसा कि नीचे उल्लेखित है

1.	सीटू ऑल इंडिया सेंटर, नई दिल्ली	–	रु० 50,000
2.	सीटू केरल स्टेट कमेटी	–	रु० 2,00,001
3.	सीटू पश्चिम बंगाल स्टेट कमेटी	–	रु० 50,000
4.	सीटू कर्नाटक स्टेट कमेटी	–	रु० 1,00,000
5.	सीटू तमिलनाडु स्टेट कमेटी	–	रु० 50,000
6.	सीटू आंध्र प्रदेश स्टेट कमेटी	–	रु० 50,000
7.	सीटू तेलंगाना स्टेट कमेटी	–	रु० 50,000
8.	ऑल इंडिया फेडरेशन ऑफ आँगनवाड़ी वर्कर्स एंड हेल्पर्स	–	रु० 87,0000
9.	ऑल इंडिया कोल वर्कर्स फेडरेशन	–	रु० 1,00,000
10.	फेडरेशन ऑफ मेडिकल रिप्रेज़ेंटेटिवस् एसोसिएशन ऑफ इंडिया	–	रु० 43,000
11.	पेट्रोलियम एंड गैस वर्कर्स फेडरेशन ऑफ इंडिया	–	रु० 50,000
12.	स्टील वर्कर्स फेडरेशन ऑफ इंडिया	–	रु० 40,000
13.	स्टील एम्पलॉईज ट्रेड यूनियनें	–	रु० 10,000
14.	वाटर ट्रांसपोर्ट फेडरेशन ऑफ इंडिया	–	रु० 50,000
15.	बैंक एम्पलॉईज फेडरेशन ऑफ इंडिया	–	रु० 45,000
16.	ऑल इंडिया स्टेट गवर्मेंट एम्पलॉईज फेडरेशन	–	रु० 43,000
17.	कन्फेडरेशन ऑफ सैंट्रल गवर्मेंट एम्पलॉयीज	–	रु० 50,000
18.	ऑल इंडिया इंश्योरेंस एम्पलॉईज एसोसिएशन	–	रु० 45,000
19.	बी.एस.एन.एल. एम्पलॉईज यूनियन	–	रु० 2,20,000
20.	कंस्ट्रक्शन वर्कर्स फेडरेशन ऑफ इंडिया	–	रु० 50,000
21.	इलेक्ट्रिसिटी एम्पलॉईज फेडरेशन ऑफ इंडिया	–	रु० 50,000
	कुल	–	रु० 14,33,001

अंतर्राष्ट्रीय स्थिति का अवलोकन

व्यवस्थागत संकटः पूरी पूँजीवादी दुनिया को अपनी चपेट में ले चुका है। यहाँ तक कि यह उन्नत औद्योगिक देशों में, विकास दर, रोजगार आदि सहित लगभग सभी आर्थिक संकेतों में दिखता है।

आर्थिक गिरावटः कोविद महामारी से पहले भी साफ नजर आ रही थी और यह लॉकडाउन के कारण और अधिक खराब हो गई। दुनिया के अधिकांश देशों ने नकारात्मक वर्षद्धि दर्ज की है। मजदूरों से उनकी नौकरी और आमदनी छिन गयी हैं। उनके वेतन और हितलाभों में कटौती की गई है।

साम्राज्यवादी आधिपत्यः साम्राज्यवादी ताकतों के नेतष्त्व वाली बड़ी आर्थिक शक्तियां आक्रामक तरीके से अपने आर्थिक, राजनीतिक और सैन्य आधिपत्य को बनाए रखने के अभियान को आगे बढ़ा रही हैं। विश्व बैंक, आईएमएफ और डब्ल्यूटीओ और विभिन्न अन्य बहुपक्षीय और द्विपक्षीय संगठनों जैसी अंतर्राश्ट्रीय एजेंसियों का उपयोग साम्राज्यवादी शक्तियों द्वारा सक्रिय रूप से किया जा रहा है।

चीन को घेरने की अमरीकी साम्राज्यवादी रणनीतिः वैश्विक स्तर पर, अमरीकी आधिपत्य को मजबूत करने के प्रयासों के तहत अमेरिका और चीन के बीच संघर्श को तेज करते हुए देखा जा रहा है, अमेरिका के 'चीन की घेराबन्दी' के लिए वैश्विक एकत्रीकरण के प्रयास, अमेरिकी रणनीतिक उद्देश्य का समर्थन करने के लिए है। संयुक्त राज्य अमेरिका और उसके साम्राज्यवादी साथी, विकासशील देशों पर अपने उत्पादों और साथ ही सट्टा पूँजी के लिए उनके बाजारों को खोलने के लिए मजबूर करने की जोड़तोड़ और दबाव डाल रहे हैं। और इन देशों की स्वदेशी उत्पादक क्षमताओं को नश्ट किया जा रहा है।

कट्टर दक्षिणपंथियों का उदयः निरंतर व्यवस्थागत संकट के दौरान कई देशों में राजनीतिक क्षेत्र में चरम दक्षिणपंथी ताकतों के उदय के साथ कामकाजी जनता के अधिकारों और आजीविका पर अत्यधिक दमनकारी हमलों को भी देखा है। इसके साथ ही, मुख्य मुद्दों से ध्यान हटाने के लिए और जनता की एकता को तोड़ने के लिए एक संदिग्ध इरादे के साथ जाति, धर्म, आप्रवासियों और कई अन्य प्रपंचों के नाम पर समाज में आक्रामक विभाजनकारी दाँव–पेंच खेले जा रहे है।

राष्ट्रीय स्थिति का अवलोकन

असामान्य और नव–सामान्यः आज हम शासक वर्गों द्वारा उनके वर्गीय हितों की सेवा के लिए बनाई गई एक 'असामान्य स्थिति' में हैं। यह अर्थव्यवस्था, शासन तंत्र, प्रशासन और समाज पर इसके आपराधिक षड्यंत्रों को वैधा बनाने के लिए 'नव–सामान्य' के रूप में उचित ठहराने का प्रयास है।

शासक वर्ग द्वारा महामारी और लॉकडाउन का फासीवादी इरादे के साथ पूरी तरह से तानाशाही की दिशा में अर्थव्यवस्था, राजनीतिक व्यवस्था और समाज के शासन के पुनर्मिाण के लिए पूँजीवादी वर्ग के हितों की सेवा करने के लिए उपयोग किया जा रहा है।

लॉकडाउन की घोशणा के बाद के घटनाक्रमों, जब देश के मजदूर और मेहनतकश जनता गंभीर संकट में हैं, अपने मजदूर विरोधी, जन विरोधी, और राश्ट्रविरोधी नवउदारवादी एजेंडा, विशेश रूप से मजदूरों और उनके ट्रेड यूनियनों के अधिकारों पर अंकुश लगाने और समाप्त करने के मामले से स्पश्ट है कि मोदीनीत भाजपा सरकार ने लॉकडाउन का उपयोग करने का एक सोचा समझा और शातिराना फैसला लिया है।

सीटू के हस्तक्षेप को आगे बढ़ाते हुए

महामारी और लॉकडाउन के बाद एक महीने के भीतर, सीटू ने कामकाजी जनता के जीवन और आजीविका पर हमले के खिलाफ सामूहिक हस्तक्षेप करने की पहल की है। देशव्यापी मुकम्मल लॉकडाउन के बीच, सीटू का पहला आह्वान 21 अप्रैल 2020 को अपने घरों के दरवाजे पर सामूहिक विरोध के लिए था, जिसको देश भर से अच्छी प्रतिक्रिया मिली थी। 21 अप्रैल के कार्यक्रम ने जमीनी स्तर पर सामूहिक हस्तक्षेपों के कई क्षेत्रीय और यूनियन स्तर की पहल थी, जिसमें ज्यादातर आजीविका के नुकसान, भुखमरी, वेतन का भुगतान न करना आदि शामिल थे। यह निचले स्तर की इकाइयों की विकेंद्रीकृत पहल थी।

इस प्रक्रिया में, ट्रेड यूनियनों के संयुक्त मंच को मजदूर वर्ग से भिड़ने वाले सभी मुद्दों पर नियमित सामूहिक कार्रवाई के लिए लाया जा सकता है। 22 मई को ट्रेड यूनियनों के संयुक्त मंच से पहला देशव्यापी विरोध प्रदर्शन हुआ था।

इसके बाद 23 और 25 सितंबर 2020 को नवीनतम आंदोलनकारी कार्यक्रमों की श्रष्ंखला जारी की गई। उल्लेखनीय है कि, कड़े लॉकडाउन की शुरुआत से लेकर अब तक की पूरी अवधि के दौरान, कामकाजी जनता के सामूहिक हस्तक्षेपों के प्रत्येक सफल कार्यक्रम में स्थानों की संख्या और मजदूरों की भागीदारी दोनों के संदर्भ में कामकाजी जनता की बड़ी लामबंदी और भागीदारी देखी गई है।

कोविड–19 महामारी के खिलाफ युद्ध में समाजवादी विचारधारा जिसने मार्गदर्शन किया

आर. करुमलैयन

कोविड–19 वायरस और वैश्विक स्तर पर इसके हमलों की लहर ने केवल मामलों की संख्या की पुष्ठि, जो अब करीब 5 करोड़ हो चुके हैं, के साथ भयावह महामारी की स्थिति पैदा कर दी है बल्कि इस तरह की आकस्मिक मानवीय जरूरतों से निपटने में पूँजीवाद और इसकी प्रासंगिकता पर बहस शुरू हो गई।

इस महामारी के हालातों में पूँजीवाद और बुनियादी मानवीय जरूरतों के बीच टकराव, विशेश रूप से स्वास्थ्य सेवा के मामले में, असाधरण तौर पर खुल कर सामने आया है। इसने स्वास्थ्य देखभाल की लागत और इसके भुगतान की क्षमता के मामले में औसत या कम आय वाले व्यक्ति के बीच के अंतर को उजागर किया है। बाजार के माध्यम से 'जरूरत' को मापना, जैसा कि नव–उदारवादी बाजार की वकालत करने वाले कट्टरपंथी करते हैं, स्वास्थ्य सेवा में पूरी तरह से विफल हुआ है, यहाँ तक कि पूँजीवादी देशों ने भी व्यापक रूप से स्वास्थ्य सेवाओं में 'कल्याणकारी राज्य' के सिद्धांत को मान्यता दी है जो कि समाजवादी सिद्धांतों की उपज है।

इस प्रकार स्वास्थ्य सेवा केवल बाजार की माँग या निजी हितों के अनुसार प्रतिक्रिया देने की सीमा परे है। इसके बजाय एक ऐसा बुनियादी ढाँचा खड़ा करने की जरुरत है जो ऐसी आपातकालीन जरूरतों को पूरा कर सके।

स्वास्थ्य सेवा में समाजवादी सिद्धांतों को चीन द्वारा असाधरण रूप से दिखाया गया है, जहाँ वुहान में केवल दो हफ्तों में तत्काल आवश्यक अस्थायी अस्पताल बनाए गए और क्वारंटीन में रहने वाले लोगों के लिए खाद्य आपूर्ति बनाए रखने की योजना भी बनाई गई थी। सहयोग की संस्कृति वाले समाजवादी दर्शिटकोण ने क्यूबा के अपनी स्वास्थ्य सेवाओं का बार–बार अन्य देशों में वहाँ की जनता के लिए, बड़े पैमाने पर, विस्तार करना संभव बनाता है।

इस प्रकार कोविद–19 महामारी ने पूँजीवादी देशों में सरकारों की सीमाओं/बाधाओं और उनकी स्वास्थ्य प्रणाली का पूरा खुजासा कर दिया है। आज यह आकलन करना कि किसने बेहतर किया है और उनकी राजनीतिक विचारधारा क्या है अधिक प्रासंगिक है।

90 के दशक में समाजवाद को झटका और नवउदारवादी युग के उदय के बाद, शेश समाजवादी देश कई चुनौतियों का सामना कर रहे हैं। फिर भी, इन समाजवादी देशों के साथ और कल्याणकारी राज्य के लिए प्रतिबद्ध देशों ने भी कोरोनोवायरस का मुकाबला बहुत अच्छे से किया।नई दिल्ली में एम्स के आर्थोपेडिक्स विभाग के प्रोफेसर (डॉ) शाह आलम खान ने अपने लेख में इन विरोधाभासों का विश्लेशण किया और कोविद–19 का मुकाबला करने में पूँजीवाद पर समाजवाद की श्रेश्ठता स्थापित की है।

माकपा की हालिया केंद्रीय समिति की बैठक में कोविद–19 का मुकाबला करने में नव–उदारवादी पूँजीवाद और समाजवाद के बीच भिन्नताओं को रेखांगित किया गया है।

केरल की एलडीएफ सरकार, समाजवादी विचारधारा वाले दलों के नेतष्त्व में, स्पश्ट रूप से भारतीय राज्यों के बीच और पूँजीवादी दुनिया में कोविद–19 महामारी का मुकाबला करने में मजबूत सार्वभौमिक सार्वजनिक स्वास्थ्य सेवा नेटवर्क के साथ मजबूती से खड़ा है, सीटू के कार्यकर्ताओं सहित अनेक कार्यकर्ता सरकार के प्रयासों में जन भागीदारी के साथ शामिल रहे हैं।

कई अन्य राज्यों में, सीटू और अन्य वामपंथी कार्यकर्ता, सीमित रूप से, मास्क, सैनिटाइजर वितरित करने और कोविड–पीड़ितों के परीक्षण और उपचार में मदद करके जनता को राहत देने में सक्रिय रहे।

कोविड–19 पर सीटू वर्किंग कमेटी की बैठक

(19–20 अक्टूबर 2020)

स्वास्थय सेवा व्यापार को बढावाः अधिकांश पूँजीवादी देशों में, लॉकडउन अवधि का उपयोग महामारी की समस्याओं को दूर करने, और जनता की भलाई के लिए राज्य के नियंत्रण में स्वास्थय सेवा नेटवर्क के विस्तार और संचालन के माध्यम से जनता की रक्षा करने के बजाय इसका उपयोग पूँजीपति वर्ग द्वारा जनता के स्वास्थ्य की आवश्यकता को, उनके बुनियादी अस्तित्व के अधिकार के बजाए, निजी स्वास्थ्य व्यवसाय, दवा कंपनियों के मालिकान और अन्य के लिए मुनाफाखोरी का कारोबार बना दिया गया है।

लोकतांत्रिक स्पेस में सिकुड़न और कामकाजी जनता पर हमलाः आम जनता के सामूहिक लोकतांत्रिक स्पेस को बुरी तरह से सीमित करने की पष्ठभूमि में, पूँजीवादी वर्ग अपने चाटुकार शासकों के माध्यम से जनता के अधिकारों और आजीविका पर सोचे–समझे आक्रामक हमले करते रहे हैं। लंबे समय तक लॉकडाउन और आर्थिक गतिविधियों में गिरावट के कारण बड़े पैमाने पर कामकाजी जनता से आजीविका, आय और आश्रय को छीन लिया गया है।

कॉरपोरेट लूट के लिएः भले ही अर्थव्यवस्था लगातार गिरावट की ओर जा रही हो, पूँजीवादी दुनिया कामकाजी जनता का और अधिक दमन करते हुए, पूँजीपति वर्ग के मुनाफों में तेज वष्द्धि के लिए आक्रामक कदम उठा रही है। यूँ ही नही है कि संयुक्त राज्य अमेरिका में 14 अरबपति लगभग 40/45 दिनों की लॉकडाउन अवधि के दौरान अपनी संचित संपत्ति को लगभग 40 प्रतिशत तक बढ़ा चुके हैं, जबकि देश की धन सष्जनता नकारात्मक दर से कम हो गई थी। यह जनता की आक्रामक लूट और राश्ट्रीय संपत्ति को उन कुछ अरबपतियों के पक्ष में दर्शाता है।

समाजवादी देशों में विरोधाभासः केवल समाजवादी देशों ने ही अन्य देशों को भी मदद करने के अलावा जनता को बचाने और महामारी को सर्वोच्च प्राथमिकता देने के साथ जन–समर्थक निरुपण को चित्रित किया।

केरल में कोविद से दो–दो हाथ करती एलडीएफः एक शत्रुतापूर्ण और भेदभावपूर्ण केंद्र सरकार के बावजूद, एलडीएफ सरकार के नेतृत्व में कोरोना के खिलाफ इस लड़ाई में देश में सबसे अच्छा प्रदर्शन करने वाला राज्य केरल है। इसमें बड़े पैमाने पर सरकारी संस्थानों को ऊपर से लेकर नीचे तक, वर्गीय एव जन संगठनों और आम जनता को शामिल किया गया।

कोविद से लड़ने में सीटूः कोविद–19 से लड़ने में, सीटू ने सभी स्तरों पर अपनी उचित भूमिका निभाई है। जब भारत में वायरस के प्रकोप ने फैलना शुरू किया, तब सर्वाधिक अनियोजित लॉकडाउन घोषित किया गया, जिससे प्रवासी मजदूरों का भारी स्थानांतरण और विस्थापन हुआ, तो सीटू ने देश भर में हस्तक्षेप करते हुए उन्हें आश्रय, भोजन आदि से हर तरह से सहायता प्रदान की।

अग्रिम पंक्ति के कार्यकर्ता कोरोना के खिलाफ इस लड़ाई में सीधे लगे हुए थे, अपने आधिकारिक कर्तव्य के अलावा आंगनवाड़ी और आशा कार्यकर्ताओं और उनकी यूनियनों ने इन मामलों में जबरदस्त काम किया। उन्होंने सफाईकर्मियों के लिए मास्क, दस्ताने, सैनिटाइजर जैसे व्यक्तिगत सुरक्षा उपकरणों की आपूर्ति की, जो पीपीई किट के बिना ही लगे हुए थे।

इसी तरह सीटू कैडर सभी संभावित तरीकों से महामारी के दौरान सबसे आगे थे।

इस प्रकार वामपंथी और दक्षिणपंथी राजनीतिक व्यवस्थाओं के बीच का बुनियादी अंतर महामारी के दौरान स्पश्ट रूप से स्थापित हो गया है।

कोविड–19 महामारी से सफलतापूर्वक लड़ने में समाजवाद मददगार हथियार साबित हुआ है

कोविड 19 को रोकने में सफल होने वाले राष्ट्र, जो वामपंथी झुकाव वाले मध्यमार्गी दलों द्वारा शासित कल्याणकारी राज्य हैं

शाह आलम खान

सर्वोच्च न्यायालय के समक्ष एक याचिका दायर की गई है, जिसमें संविधान की प्रस्तावना से 'समाजवादी' और 'पंथनिरपेक्ष' शब्दों को हटाने की माँग की गयी है। लेकिन पिछले कुछ दशकों में लगातार गिरावट के बावजूद, दोनों सिद्धान्त उस प्रकार के लिए गणतंत्र के केंद्रीय थे जैसे की कल्पना हमारे राजनीतिक पूर्वजों ने की थी। नब्बे के दशक में नवउदारवादी नीतियों को अपनाने के साथ, समाजवाद को एक तरफ धकेल दिया गया। हालांकि, वर्तमान में चल रही महामारी के साथ, समाजवाद न केवल भारत के लिए, बल्कि दुनिया के लिए भी प्रासंगिक हो गया है। जैसा कि दुनिया कोविड–19 के लिए एक वैक्सीन खोजने के लिए जूझ रही है, महामारी के परिणामों के एक करीबी निरीक्षण से पता चलता है कि समाजवादी आदर्श जीवन–रक्षक बन गए हैं। इसके लिए और अधिक पुष्टि एवं मूल्यांकन की आवश्यकता है।

नवउदारवादी दुनिया में, शायद ही कोई देश विशुद्ध समाजवादी राष्ट्र के रूप में प्रतिष्ठित हो सकता है। वे देश जो सामाजिक रूप से स्वास्थय सेवाएं प्रदान करते हैं, वे हैं जिन्होंने एक कल्याणकारी राज्य कहे जाने वाले मॉडल को विकसित किया है अर्थात् अतीत के समाजवादी राज्य के करीबी रिश्तेदार हैं।

कोविड–19 महामारी ने सरकारों, स्वास्थय सेवा ढाँचों और राजनीतिक विचारधाराओं की नाजुकता को उजागर किया है। इस प्रकार यह देखना महत्वपूर्ण है कि किन देशों ने इस महामारी के दौरान कोविड से संबंधित रुग्णता और मृत्यु दर दोनों के संदर्भ में बेहतर प्रदर्शन किया है। और उनकी सत्ता की राजनीतिक विचारधारा क्या है।

यह कल्पना करना कोई मुश्किल नहीं है कि अच्छे स्वास्थ्य के बुनियादी ढाँचे वाले देश ही महामारी के दौरान बेहतर काम करेंगे। यह कहने के बाद, महामारी की प्रतिक्रिया और परिणाम के मापदंडों ने ऐसे सरल रुझान नहीं दिखाए हैं। स्वास्थ्य सेवा प्रबंधन के अलावा, इसमें राजनीतिक प्रतिक्रिया और इच्छाशक्ति भी शामिल है।

एक अच्छी सार्वजनिक स्वास्थ्य प्रणाली की अवधारणा और उसका अमल, जो समाजवाद के किसी भी रूप का एक महत्वपूर्ण घटक है, वर्तमान महामारी के दौरान एक बेहतर परिणाम दिखाता है। निजी स्वास्थ्य सेवाओं के साथ पूँजीवादी प्रणालियों ने अत्याधुनिक स्वास्थ्य सेवा की उपलब्धता के मामले में एक अच्छे स्वास्थ्य ढाँचे के बावजूद सबसे खराब प्रदर्शन किया है। संयुक्त राष्ट्र अमरीका अभी का एक उत्कृष्ट उदाहरण है।

वर्तमान महामारी के बारे में अच्छी प्रतिक्रिया के संदर्भ में, एक देश जो ऑस्ट्रेलिया के क्षेत्र में है, वह न्यूजीलैंड है। न्यूजीलैंड में कोविड–19 आंकड़े लगभग 1,757 मामलों और 4.56 प्रति दस लाख मामलों की कम मृत्यु दर के साथ दुनिया में सबसे अच्छा हैं। देश वर्तमान में लेबर पार्टी द्वारा शासित है, जिसका झुकाव मध्यमार्ग से वामपंथ की ओर है। न्यूजीलैंड में सकल घरेलू उत्पाद के प्रतिशत के रूप में स्वास्थ्य पर कुल व्यय लगभग 11 प्रतिशत है। भारत के लिए, इसकी प्रस्तावना में 'समाजवाद' होने के बावजूद, यह आंकड़ा एक प्रतिशत ही है।

अधिकांश यूरोपीय राश्ट्र जिन्होंने वर्तमान महामारी में अच्छा प्रदर्षन किया है, वे समाजवादी झुकाव या सत्ता में वाम गठबंधन के साथ पूरी तरह से कल्याणकारी राज्य हैं। जर्मनी में महामारी का तेजी से प्रकोप था लेकिन मौत को उतनी तेजी से रोकने में सक्षम था। अब तक, जर्मनी में कुल 2,47,000 मामले दर्ज किए गए, जिनमें से मष्त्यु दर प्रति दस लाख में 108 ही है। स्वास्थ्य पर जर्मनी का कुल व्यय जीडीपी का लगभग 11 प्रतिशत है और यह स्वास्थ्य पर यूरोपीय संघ के अन्य देशों द्वारा खर्च किए गए औसत से लगभग एक प्रतिशत अधिक है। पुर्तगाल ने, जहाँ पिछले कुछ वर्षों से वामपंथी गठबंधन की सरकार रही है, महामारी को अच्छी तरह से संभाला है। कई अन्य यूरोपीय देशों की तुलना में इसकी लोकतांत्रिक रूप से नियोजित लॉकडाउन को आसानी से खोल दिया गया था। इसमें 1,827 मौतों के साथ कुल 58,000 मामले थे। यह पड़ोसी देश स्पेन के विपरीत था, जो कि 4,80,000 मामलों और 29,194 मौतों के कारण वायरस से तबाह हो गया था। स्वास्थ्य पर पुर्तगाल का कुल व्यय जीडीपी का 9.5 प्रतिशत है। फिर भी एक अन्य यूरोपीय राष्ट्र जिसने महामारी से निपटने में अच्छा काम किया कुल 2,121 मामले और 10 मौतों के साथ आइसलैंड है। दिलचस्प बात यह है कि आइसलैंड निवासियों ने 2017 में आम चुनावों में बहुमत वाली वामपंथी सरकार को वोट दिया।

लैटिन अमेरिकी देशों में भी, स्वास्थ्य पर अधिक खर्च करने वालों ने उन लोगों की तुलना में बेहतर प्रदर्शन किया है जो जन केंद्रित कार्यक्रमों पर खर्च करने में कंजूस हैं। अर्जेंटीना एक उत्कृष्ट उदाहरण है। 40,000 कोविड–19 मामलों और 8,00 मौतों के साथ, यह अपने अधिकांश पड़ोसियों की तुलना में कहीं बेहतर है। देश में पेरोनियों का शासन है, जो अधिक वामपंथी आर्थिक नीतियों को अपनाते हैं। अर्जेंटीना की आबादी अपने पड़ोसी ब्राजील में कई मामलों में तुलनीय है, जिसमें दक्षिणपंथी सरकार है और 3 करोड़ 96 लाख मामले और लगभग 1.23 लाख मौतों के साथ वायरस से तबाह हो गया है। दूसरी ओर वेनेजुएला ने, जो पिछले दो दशकों से समाजवादी शासन के अधीन है, वर्तमान महामारी के दौरान आशाजनक परिणाम दिखाये। इसमें केवल 400 मौतों के साथ 47,756 मामले सामने आए।

इस परिकल्पना के खिलाफ एक तर्क यह होगा कि न्यूजीलैंड, जर्मनी, आइसलैंड या यहाँ तक कि अर्जेंटीना के साथ भारतीय स्थिति की तुलना करना मुश्किल है क्योंकि हमारी आबादी इन देशों की संयुक्त आबादी से भी अधिक है। बाजारु अर्थव्यवस्था के समर्थकों के साथ समस्या यह है कि वे सभी समस्याओं को जनसंख्या वृद्धि पर लाद देते हैं। वर्तमान महामारी में सबसे अच्छा प्रदर्शन करने वाला भारतीय राज्य केरल भी सबसे अधिक आबादी वाला है। जनसंख्या वृद्धि की चिंता हमेशा एक लोकलुभावन एजेंडे का हिस्सा रही है, जिसमें गरीबों की आबादी मुख्य चिंता का विषय है। हम यह समझने में विफल हैं कि जनसंख्या के स्थरीकरण का मार्ग जनता के समग्र सामाजिक–आर्थिक विकास से होकर गुजरता है, और इस कोविड–19 महामारी ने इसका बहुत अच्छी तरह से खुलासा किया है।

निष्कर्ष निकालने के लिए, एक तीखी नजर से पता चलता है कि समाजवाद एक अजीब जुगाड़ नहीं है जो अलग हो जाए। यहाँ तक कि इसके सबसे अधिक निष्क्रिय, रूपांतरित, बेमेल रूप में भी, यह कोविड–19 महामारी से सफलतापूर्वक लड़ने में एक असरदार हथियार रहा है। समाजवादी व्यवस्था के लिए भारत की खोज भले ही निरर्थक रही हो, लेकिन समाजवादी सिद्धांत हमारे जैसे देश में भी जनता के स्वास्थ्य से संबंधित मुद्दों के बारे में आशा की एक झलक प्रदान करते हैं।

लेखक अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान के ऑर्थोपेडिक्स विभाग में प्रोफेसर हैं।

(सौजन्य से: इंडियन एक्सप्रेस; 19 अक्टूबर, 2020)

माकपा की केन्द्रीय कमेटी की बैठक की रिपोर्ट से

(30–31 अक्टूबर 2020)

विश्व स्तर पर कोविद–19 महामारी के हालात

दुनिया भर में पुष्ट कोविद मामलों ने 4 करोड़ को पार कर लिया है। हालांकि, विशेशज्ञों ने चेतावनी दी कि यह तो असल संकट का केवल अंश मात्र ही है।

इस क्रम में *संयुक्त राज्य अमेरिका, भारत* और *ब्राजील* ने सबसे अधिक मामलों और मौतों की रिपोर्ट जारी की है। चिंता की बात है कि भारत में पॉज़िटिव मामलों और मौतों दोनों की वृद्धि दर आज दुनिया में सबसे अधिक है।

कई देश जैसे कि *ब्रिटेन, फ्रांस, रूस, स्पेन* आदि, जो यूरोप में लगभग सात लाख के साप्ताहिक बढ़ोतरी का सबसे अधिक योगदान दर्ज करा रहे हैं, अब विभिन्न चरणों के लॉकडाउन को फिर से लागू कर रहे हैं।

समाजवादी देश

इसके विपरीत, समाजवादी देश महामारी को फैलने से रोकने और आर्थिक गतिविधियों और सामान्य जीवन को फिर से शुरू करने में सक्षम रहे हैं।

अक्टूबर तक, *चीन* ने 85,000 से अधिक मामलों और 4,634 लोगों की मौत की सूचना दी। लगभग 3 करोड़ पार्टी सदस्यों ने महामारी से लड़ने के लिए मोर्चे पर सक्रिय रूप से भाग लिया। पार्टी के 396 सदस्यों ने इस प्रक्रिया में अपनी जान कुर्बान की है।

क्यूबा ने महामारी के कारण 123 लोगों को खो दिया। क्यूबा अपने उपर अमेरिकी आर्थिक नाकाबंदी के बावजूद, देश में महामारी को रोकने और बड़ी संख्या में जनता की जान बचाने में सक्षम रहा है।

वियतनाम में, अब तक 139 लोग अपनी जान गंवा चुके हैं और यह देश में उठी दूसरी लहर को सफलतापूर्वक रोकने करने में सक्षम था। वियतनाम की सरकार ने जनता के लिए सभी आवश्यक वस्तुओं को मुफ्त में खरीदने के लिए साप्ताहिक सुपर बाजार शुरू किए। इसने चावल के एटीएम भी शुरू किए हैं जहाँ लोग मुफ्त में चावल ले सकते हैं।

हाल ही में बाढ़ और तूफान से हुई तबाही के बावजूद *डीपीआरके* देश में शून्य मौतों की सूचना दे रहा है। राहत और पुनर्वास के भारी प्रयास पर महामारी के प्रसार का कोई असर नहीं हुआ।

इस पैमाने पर, नवउदारवादी पूँजीवाद और समाजवाद के बीच का बुनियादी अंतर इस अवधि के दौरान एक बार फिर स्थापित हो गया है।

टीका

दुनिया की बहुप्रतीक्षित कोरोनो वायरस वैक्सीन को शक्तिशाली और सुरक्षित बनाए रखने के लिए लगातार विसंक्रमित ठण्डक में रखने की आवश्यकता होती है। जबकि एक अनुमान के अनुसार दुनिया के 78 खरब लोगों में से लगभग 0.3 खरब उन जगहों पर रहते हैं जहाँ कोविद–19 को नियंत्रण में लाने के एक टीकाकरण अभियान के लिए तापमान नियंत्रित भंडारण की उचित व्यवस्था ही नहीं है। जबकि यह वायरस अंधाधुंध प्रहार करता है, इस महामारी की चपेट में आने वाले दुनिया के गरीब लोग हैं जो कि इससे उबरने वालों में अंतिम भी हो सकते हैं। यह स्थिति वैक्सीन विकसित होने पर भी महामारी के पूरे नियंत्रण में आने तक की इसकी व्यापकता को लम्बा खींच देगी।

बोलिविया की नयी संसद

50 प्रतिशत से अधिक महिला सासंद

संसद में महिलाओं के प्रतिनिधित्व के मामले में रवांडा और क्यूबा के बाद बोलीविया दुनिया में तीसरे स्थान पर है।

बोलीविया में हाल ही में हुए चुनावों में न केवल समाजवादी दलों ने सत्ता में वापसी की बल्कि संसद के दोनों सदनों–चैम्बर ऑफ रिप्रेजेंटेटिव व सीनेट में अधिक महिला विधायक चुनकर आयी हैं।

इवो मोरालेस की पार्टी मूवमेंट फॉर सोशलिज्म (एमएएस) ने बोलिविया के प्रेजीडेंशियल चुनावों में जीत दर्ज की है। यह बोलीविया की लोकतांत्रिक ताकतों और इसकी मूल आबादी के लिए एक बड़ी जीत है, जिन्होंने पिछले साल अमेरिका की मदद से दक्षिणपंथी अंतरिम सरकार द्वारा तख्तापलट के बाद भारी दमन का सामना किया था।

टेलीसर के अनुसार, एमएएस ने 21 सीटों के साथ सीनेट में बहुमत हासिल किया, जिनमें 10 महिलाएं है। सिटीजन कम्युनिटी ने 11 सीटें जीतीं, जिनमें सात महिलाऐं है, तथा 'वी बिलीव' ने चार सीटों पर विजय प्राप्त की जिनमें दो महिलाए है।

चैम्बर ऑफ रिप्रेजेंटेटिव में 48.33 प्रतिशत प्लुरिनोमिन्यल्स पुरुष हैं तथा 51.6 प्रतिशत महिलायें है। इस बीच 57.14 प्रतिशत सीटों के साथ यूनिनोमियल्स में महिलाओं का दबदबा पुनः कायम हो गया है।

57.14 प्रतिशत के साथ मूल वासियों का प्रतिनिधित्व महिलायें करेंगी। सुप्रा स्टेट रिप्रेजेंटेटिव में भी 55.56 महिलाएं हैं।

चुनी गई महिला सांसदों में एक बड़ी संख्या नये चेहरों की हैं, जो अपनी महिला प्रतिनिधियों में मतदाताओं के भरोसे को दिखाता है।

ऐसा कैसे हुआ?

बोलीविया की राजनीति में महिलाओं का प्रतिनिधित्व कोई नई बात नहीं है। इस बारे में 2014 के चुनाव ऐतिहासिक थे जब लेजिस्लेटिव असेम्बली में 51 प्रतिशत महिलायें चुनकर आई थी। पॉलिटिकल कान्सटीट्यूशन ऑफ बोलीविया (2009) का पारित होना, संबंधित कानूनों के बनने के साथ अलग अलग महिला आंदोलनों में महिलाओं की लगातार व्यापक लामबंदी ने महिलाओं और पुरुषों के बीच अधिक बराबरी पर आधारित हिस्सेदारी के सिद्धांतों को मान्यता व उनके अमल का काम किया। असेम्बली के 166 सदस्यों में 82 महिलाओं का चुना जाना बोलीविया के इतिहास में सबसे अधिक है। लोकतंत्र के 32 वर्षों के बाद, देश 1982 के 2 प्रतिशत प्रतिनिधित्व से आगे बढ़कर राष्ट्रीय संसद के राजनीतिक परिदृश्य में बराबरी तक पहुंच गया है।

राजनीति में महिलाओं का प्रतिनिधित्व

इंटर पार्लियामेंट्री यूनियन व युनाइटेड नेशंस के मैप ऑफ वुमेन इन पॉलिटिक्स के अनुसार, संसद में महिलाओं के प्रतिनिधित्व के मामले में बोलीविया, रवांडा और क्यूबा के बाद दुनिया में तीसरे स्थान पर है।

संसद में महिलाओं के प्रतिनिधित्व के मामले में रवांडा का रिकॉर्ड सबसे अच्छा है, जहाँ संसद की लगभग दो तिहाई सदस्य महिलायें हैं।

दो और ऐसे देश हैं जहाँ संसद में महिलाओं की संख्या पुरुषों से अधिक है – क्यूबा (53.2 प्रतिशत) और बोलीविया (53.1 प्रतिशत)। प्रथम 10 में से अगले चार स्थान लैटिन अमेरिकी और कैरेबियाई राष्ट्रों के पास हैं – मैक्सिको (48.2 प्रतिशत), ग्रेनेडा (46.7 प्रतिशत), निकारागुआ (45.7 प्रतिशत) और कोस्टारिका (45.6 प्रतिशत)।

शीर्ष 10 के शेष दो अफ्रीकी देश है– नामीबिया (46.2 प्रतिशत) और दक्षिण अफ्रीका (42.7 प्रतिशत) – और, आश्चर्यजनक है कि (46.1 प्रतिशत) के साथ स्वीडन की सरकार पहली है जिसने अपने आपको 'नारीवादी' सरकार होने का दावा किया है।

देशों का नॉर्डिक समूह 42.3 प्रतिशत सीटों के साथ महिला प्रतिनिधित्व का मार्ग प्रशस्त करता है, इसके बाद अमेरिका (30.3 प्रतिशत), शेष यूरोप (26.5 प्रतिशत), और उप–सहारा अफ्रीका (23.8 प्रतिशत) हैं। एशिया (19.7 प्रतिशत) और अरब राज्य (18.7 प्रतिशत) वैश्विक औसत से काफी नीचे हैं, लेकिन प्रशांत राष्ट्रों (15.5 प्रतिशत) का सबसे खराब रिकॉर्ड है।

महिला प्रतिनिधित्व का महत्व

कई निर्वाचन प्रणाली में विधायक और सांसद के रूप में अधिक महिलाओं के साथ कोटा एक आम कारक है। 1991 में कानून द्वारा लिंग कोटा लागू करने वाला दुनिया का पहला देश अर्जेंटीना था। तब से पार्टियों के लिए महिला उम्मीदवारों के एक निश्चित अनुपात को आगे बढ़ाने की कानूनी आवश्यकता लैटिन अमेरिका में और इसके परे भी आम हो गई है। कई अन्य देशों ने एक ही उद्देश्य के साथ अलग–अलग दृष्टिकोण अपनाए हैं, या तो महिलाओं (चीन, पाकिस्तान और कई अरब देशों में) के लिए सीटें आरक्षित कर, या राजनीतिक दलों ने स्वेच्छा से अपने स्वयं के कोटे (यूरोप के बहुत से) को अपनाया है।

कोटे ने निश्च्चत रूप से रवांडा की राजनीति पर एक नाटकीय प्रभाव डाला। 1990 के दशक में औसतन 18 प्रतिशत संसदीय सीटें महिलाओं के पास थीं। 2003 के संविधान में 30 प्रतिशत निर्वाचित पदों पर महिलाओं का होना अनिवार्य है। 2008 तक महिलाओं ने रवांडा की संसद का आधे से अधिक हिस्सा बनाया, और यह अनुपात 2013 के चुनाव में लगभग दो–तिहाई हो गया।

पिछले 20 वर्षों में, अधिक से अधिक महिला प्रतिनिधित्व की दिशा में बड़े कदम उठाए गए हैं। 1997 में महिलाओं के पास केवल स्वीडन, नॉर्वे, फिनलैंड, डेनमार्क और नीदरलैंड में 30 प्रतिशत से अधिक सीट थी। अब ऐसे 49 देश हैं, जहाँ उस सीमा को तोड़ दिया गया है। लेकिन 2015 के बाद से प्रगति रुक गई है – और कुछ मामलों में उल्टा हो गया है।

किसानों, महिलाओं, समुदाय के नेताओं, शिक्षाविदों जैसे विभिन्न क्षेत्रों के व्यक्तियों का प्रतिनिधित्व एक अधिक न्यायसंगत समाज के विकास को सुनिश्चित करता है। महिलाओं का प्रतिनिधित्व महिलाओं के उत्पीड़न और लिंग आधारित हिंसा को रोकने के लिए नियम बनाने में मदद करता है।*(सौजन्यः गौरी लंकेष न्यूज डेस्क; 30 अक्टूबर 2020)*

आत्म–निर्भर भारत के लिए संघर्ष

जे.एस. मजुमदार

कोविद –19 महामारी के दौरान, 'आत्मानिर्भर भारत' प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का नया राजनीतिक नारा है।

राष्ट्रीय स्वतंत्रता संग्राम से उभरे 'आत्मनिर्भर भारत' या 'सेल्फ–रिलाइन्ट इण्डिया' और यद्यपि आज निष्क्रिय है, लेकिन भारत की जनता की साम्राज्यवाद–विरोधी चेतना में बना हुआ है। हालाँकि आरएसएस और उसके राजनीतिक दल के अवतारों ने कभी भी राष्ट्रीय स्वतंत्रता संग्राम में भाग नहीं लिया था, लेकिन मोदीजी ने इसे एक संभावित विपणन नारे के रूप में महसूस किया। इसलिए, उन्होंने अपने पहले के 'मेक इन इंडिया' प्रोजेक्ट को 'आत्मानिभर भारत' प्रोजेक्ट के रूप में पुनः पेश कर दिया। मोदीजी की विकास परियोजना 'आत्मनिर्भर भारत' की सामग्री भी वैसी ही है जैसी कि 'मेक इन इंडिया' की ही रही है। जो अंतर्राश्ट्रीय वित्तीय पूँजी और आईएमएफ, विष्व बैंक, विष्व व्यापार संगठन नामक तिकड़ी के निर्देशन में नव–उपनिवेशवाद के तानाषाहीपूर्ण आर्थिक विकास को व्यापक प्रसार और अधिक तीव्रता के साथ आक्रामक रूप से लागू करने के लिए है। और यह उस 'सेल्फ–रिलाइन्ट इण्डिया' के विपरीत है, जिसके लिए भारत की जनता ने लड़ाई लड़ी थी।

मोदीजी आयी कोविद महामारी के साथ जल्दी में हैं। नीति आयोग कोविद उपरान्त और चीनी व्यापार पर ट्रम्प के हमले के मद्देनजर अंतर्राश्ट्रीय कॉरपोरेट्स के चीन से पलायन, और भारत में उन्हें आमंत्रित करने के अवसर का पूर्वानुमान लगा रहा है। 'नमस्ते ट्रम्प' का आयोजन किया गया और कोविद लॉकडाउन की घोशणा में देरी की गयी और फिर बिना किसी तैयारी के ही घोषणा की गई थी। मजदूर विरोधी व कॉरपोरेट हितैषी श्रम कानूनों और कृशि क्षेत्र के कॉरपोरेटीकरण के लिए अध्यादेष/कार्यकारी आदेष जारी किए गए और विधेयकों को विपक्ष–मुक्त संसद में पारित किया गया।

उनके और कुछ अन्य के नेतष्त्व में, राज्य सरकारें, 'आत्मनिर्भर भारत' परियोजना के तहत, अंतर्राष्ट्रीय कॉरपोरेटस् के काल्पनिक पलायन को आमंत्रित करने की होड़ में, श्रम कानूनों में संषोधन करके, सभी मौजूदा उद्योगों में काम का बोझ बढ़ाकर, मजदूरों पर शोषणकारी कामकाजी शर्तें थोपकर, और नये उद्योगों को श्रम–कानूनों से मुक्त करने में लगी हुई हैं।

इसलिए, ऐतिहासिक परिप्रेक्ष्य में राष्ट्रीय स्वतंत्रता आंदोलन में विकसित 'आत्मनिर्भर भारत' या 'सेल्फ–रिलाइन्ट इण्डिया' की विषय वस्तु और दिशा को समझना आवश्यक है।

राश्ट्रीय स्वतंत्रता आंदोलन जैसे–जैसे उन्नत हुआ था, यह महसूस किया गया कि राजनीतिक स्वतंत्रता पर्याप्त नहीं थी। उपनिवेषवाद के तहत विद्यमान षाही पूँजी से भी आर्थिक स्वतंत्रता प्राप्त होनी चाहिए और स्वतंत्र भारत में अपने आर्थिक विकास में देष को आत्मनिर्भर बनाने और इससे 'सेल्फ–रिलाइन्ट इण्डिया' की अवधारणा उभरकर सामने आई।

स्वतंत्रता पूर्व की अवधि में, स्वतंत्रता के बाद 'सेल्फ–रिलाइन्ट इण्डिया' के लिए आर्थिक विकास का एक स्वरुप प्रस्तुत करने के लिए कुछ संगठनात्मक पहलें हुईं थी। इसी तरह की एक संगठनात्मक पहल देष के शीर्ष उद्योगपतियों द्वारा की गई थी। उन्होंने इस स्वरुप को प्रस्तुत किया जिसे इतिहास में 'बॉम्बे प्लान' के नाम से जाना जाता है।

'सेल्फ-रिलाइन्ट इण्डिया' का एक स्तंभः सार्वजनिक क्षेत्र

ब्रिटिश सरकार द्वारा विश्वासघात और अभाव

जुलाई 1944 में आयोजित संयुक्त राष्ट्र मौद्रिक सम्मेलन, जिसे आमतौर पर ब्रेटन वुड्स सम्मेलन के रूप में जाना जाता है; में सात सदस्यीय भारतीय प्रतिनिधिमंडल में एक गैर–सरकारी प्रतिनिधि, अर्देशिर दर्भश श्रॉफ एक परेशान आदमी

था। ब्रेटन वुड्स सम्मेलन में, द्वितीय विश्व युद्ध में गंभीर रूप से क्षतिग्रस्त वैश्विक पूँजीवाद के पुनर्निर्माण के लिए और विश्व युद्ध के बाद की स्थिति में पूर्व–औपनिवेशिक देशों में नव–औपनिवेशिक शोषण के लिए आईएमएफ और विश्व बैंक का निर्माण किया गया था। इसके बाद 1948 में जीएटीटी बनाया, और फिर 1995 में इसे अधिक कठोर शर्तों के साथ बदलकर डब्ल्यूटीओ कर दिया ताकि संप्रभु राष्ट्रों पर इसके निर्णय को जबरन थोपा जा सके।

श्रॉफ उस समय के षीर्श भारतीय उद्योगपतियों के एक चयनित समूह के प्रवक्ता थे, जिन्होंने पहले जनवरी 1944 में बॉम्बे प्लान को अपनाया था। वे उम्मीद कर रहे थे कि भारत की स्वतंत्रता के बाद के आर्थिक विकास के लिए ब्रिटेन की बड़ी ऋण राषियां मुख्य स्रोत होंगीं।

ब्रेटन वुड्स सम्मेलन में, ब्रिटेन के युद्ध के बाद के ऋण को भारत के बहुपक्षीय परिवर्तनीयता में जोड़ने के श्रॉफ के प्रस्ताव वोटिंग में गिरा दिया गया था। यहाँ तक कि परिवर्तनीयता को हटाने के लिए सम्मेलन पूर्व के व्हाइट प्लान को भी छोड़ दिया गया था। षीत युद्ध में अमेरिका–ब्रिटेन–फ्रांस गठबंधन की पृश्ठभूमि में, समाजवादी देषों की प्रगति को अवरुद्ध करने के वास्ते, अब अपने आर्थिक सिद्धांत के लिए प्रसिद्ध केन्स के नेतृत्व में यूके प्रतिनिधिमंडल ने यूएस–यूके गुप्त सौदा किया जिससे के चलते भारत की उम्मीद बदल गयी।

3.5 करोड़ पाउंड की एक छोटी सी पहली किस्त के बाद, यूके ने भारत को अपने भारी ऋण का भुगतान कभी नहीं किया। भारत का रुका हुआ 151 करोड़ स्टर्लिंग पाउंड था जो 2018 में 8393 करोड़ डालर के बराबर है। इस ऋण का एक तिहाई से अधिक भारत की निर्यात आय से था, जिसे वापस लंदन में रोक लिया गया था; और दो तिहाई षाही युद्ध के लिए भुगतान करने का था और 25 लाख भारतीय सैनिकों के लिए जो दुनिया के विभिन्न हिस्सों में युद्ध लड़ रहे थे, भारत के भोजन, सहयोगियों के लिए, लड़ाई का सामान, सैन्य वाहनों और अन्य उपकरणों की आपूर्ति का भी था।

दूसरी ओर, युद्ध को भारी टैक्सों के द्वारा वित्तपोषित किया, धन की आपूर्ति में वषद्धि की गयी और औपनिवेशिक सरकार द्वारा उधार लिया गया; भारत की जनता पर राहदारी थोपी गयी, जिसने तेज से महंगाई, व्यापक बिखराव और भारी निजीकरण को बढ़ा दिया। ब्रिटिष सेना की आपूर्ति के कारण खरीद क्षमता में भार गिरावट आयी और खाद्यान्नों की अनुपलब्धता हई, 1943 के बंगाल अकाल में लगभग 30 लाख लोगों की मष्त्यु हो गई। यूएस–यूके गुप्त सौदे के हिस्से के रूप में, संयुक्त राश्ट्र राहत और पुनर्वास के तौर पर भारत को खाद्य सहायता प्रदान करने के लिए भी अनुमति नहीं दी अमेरिकी कानून पीएल267 पर ब्रिटिष सरकार ने रोक लगा दिया। यूएस–यूके के विष्वासघात ने भारत को कहीं और से फंड की तलाष करने के लिए मजबूर किया।

बॉम्बे प्लान और सार्वजनिक क्षेत्र का उद्भव

जनवरी 1944 में 'बॉम्बे प्लान' जिसे *ए ब्रीफ मेमोरेंडम आउटलाइनिंग प्लान ऑफ इकोनॉमिक डेवलपमेंट ऑफ इंडिया'* का शीर्षक दिया गया, के हस्ताक्षरकर्ता षीर्श उद्योगपति जेआरडी टाटा, जीडी बिड़ला, ए. दलाल, लाला श्रीराम, कस्तूरभाई लालभाई, ए.डी. श्रॉफ, पुरुषोत्तमदास ठाकुरदास और जॉन मथाई थे। मार्च 1944 में, फेडरेशन ऑफ इंडियन चौंबर्स ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री (फिक्की) ने अपनी वार्षिक बैठक में इस योजना का समर्थन किया।

योजना का उद्देश्य प्रति व्यक्ति की आमदनी को दोगुना करना; 15 वर्षों में मुख्य रूप से ब्रिटिश ऋण अदायगी के वित्तपोषण से 1000 करोड़ निवेश (उद्योग के लिए 44.8%) के साथ कृषि उत्पादन को दो गुना और पाँच गुना औद्योगिक विकास करना था।

बॉम्बे प्लान का मुख्य आधार यह था कि अर्थव्यवस्था सरकारी हस्तक्षेप और विनियमन के बिना विकसित नहीं हो सकती;विदेशी प्रतिस्पर्धा के खिलाफ भारतीय उद्योग को सरकारी संरक्षण की आवश्यकता थी; और निजी क्षेत्र के पास निवेष के लिए पर्याप्त धन और वास्तविक उत्पादन के लिए लंबी अवधि का इन्तजार नहीं था, महत्वपूर्ण उद्योगों की

स्थापना सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यम के रूप में और उपभोग के अंतिम उत्पादन के लिए निजी क्षेत्र की सेवा तय की गयी।

परिणाम स्वरुप 1950 में प्रथम पंचवर्शीय योजना, जिसके बाद 1956 में औद्योगिक नीति प्रस्ताव संसद द्वारा पारित किया गया, जिसने उद्योगों के सभी प्रमुख क्षेत्रों में सार्वजनिक उपक्रमों का प्रस्ताव किया। अन्य भी विचाराधीन थे; जैसे कि भारत में पूँजीवादी अर्थव्यवस्था के विकास के लिए, बिना किसी सतत सम्बद्धता और व्यावसायिक हित के ही, उपभोग योग्य (टर्नकी) के आधार पर प्रमुख क्षेत्र के उद्योगों में सार्वजनिक उद्यमों की स्थापना के लिए, समाजवादी देशों से प्रौद्योगिकी, निधि आदि का लाभ उठाया जाऐ।

इस प्रकार प्रमुख क्षेत्रों में सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यम स्वाबलम्बी–भारत के स्तंभ के रूप में उभरे और जनता की राश्ट्रीय संपत्ति बन गए।

विश्वासघात

दूसरी तरफ, निजी क्षेत्र ने मुनाफे में वषद्धि की और षीर्श औद्योगिक घरानों ने अपनी संपत्ति में बड़ी वषद्धि की और आजादी के बाद से नए औद्योगिक घराने उभर आए। तीन दषकों के भीतर उनके पास इतना धन जमा हो गया कि सार्वजनिक उद्यमों को कौड़ियों के दाम सौंपने की माँग करने लगे। इस प्रकार उन्होंने स्वाबलम्बी–भारत की अपनी ही योजना को धोखा दिया।

उनका प्रतिनिधित्व करने वाले राजनीतिक दलों ने भी राश्ट्रीय स्वतंत्रता आंदोलन के इस वादे को धोखा दिया। इन सार्वजनिक उपक्रमों के रखरखाव, विस्तार और उन्हें अपडेट करने में लगातार उपेक्षा होती रही है। एक के बाद दूसरी सरकारों ने सार्वजनिक क्षेत्र और अर्थव्यवस्था की बुनियादी संरचना को कमजोर कर दिया। और बाद में, उन्होंने प्रचार करना शुरू कर दिया कि सार्वजनिक क्षेत्र आर्थिक विकास का 'समाजवादी' दृष्टिकोण है।

भारत में सार्वजनिक क्षेत्र समाजवादी एजेंडा नहीं है। यह पूँजीवादी व्यवस्था में 'स्वाबलम्बी–भारत' के मूल में है। सार्वजनिक क्षेत्र सरकार की पूँजी का प्रतिनिधित्व करता है। यह निर्भर करता है कि शासन कौन से वर्ग या वर्गों का है। भारतीय स्थिति में, सार्वजनिक क्षेत्र को शीर्ष उद्योगपतियों द्वारा प्रस्तावित किया गया था और यह फिक्की का एजेंडा था। जवाहरलाल नेहरू ने इसे 'मिश्रित अर्थव्यवस्था' कहा, जो किसी भी आर्थिक सिद्धांत में मौजूद नहीं है।

अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय पूँजी के हुक्म पर उदारीकरण, निजीकरण और वैष्वीकरण की नवउदारवादी आर्थिक नीति को भारत सरकार द्वारा 1990 के दशक की षुरुआत में अपनाया गया, और घरेलू एवं अंतर्राष्ट्रीय दोनों तरह के निजी संपत्ति धारकों की खातिर जनता की सम्पत्ति सार्वजनिक क्षेत्र पर हमले किए हैं।

सार्वजनिक क्षेत्र की रक्षा में मजदूर वर्ग द्वारा प्रतिरोध आन्दोलन

यह भारत का मजदूर वर्ग ही है, जो अन्य मेहनतकष तबकों के समर्थन के साथ सार्वजनिक क्षेत्र और 'स्वाबलम्बी–भारत' अर्थात् 'आत्मानिभर भारत' की रक्षा के लिए लड़ रहा है और बचाव कर रहा है। पिछले 3 दषकों के दौरान 19 आम हड़तालें और 26 नवंबर 2020 की आने वाली आम हड़ताल और असंख्य आम एवं सेक्टरवार प्रतिरोध आंदोलन इसकी गवाही हैं।

इसकी हालिया गवाही कोयला मजदूरों की 3 दिवसीय हड़ताल है जिसने सरकार को पीछे धकेला है, बार–बार वाणिज्यिक प्रयोजनों के लिए कोयला खदानों की नीलामी की तारीखों के आगे बढ़ाती रही है जिसे खुद पीएम ने उद्घाटन किया था; और सार्वजनिक क्षेत्र की कोयला कंपनियों की रक्षा में; प्रतिरक्षा क्षेत्र के कर्मचारियों का आन्दोलन और उनकी 12 अक्टूबर 2020 से प्रस्तावित अनिष्चितकालीन हड़ताल (और अस्थायी रूप से प्रतिरक्षा उत्पादन के निरोध की प्रक्रिया को समाप्त करने का समझौता); और आउटसोर्सिंग के खिलाफ; परिवहन कर्मचारियों द्वारा हड़ताल और आंदोलन में; बिजली कर्मचारियों के आंदोलन में; बीपीसीएल में हड़ताल और तेल क्षेत्र में आंदोलन; पोर्ट एंड डॉक श्रमिकों की हड़ताल;

बैंक कर्मचारियों, बीमा कर्मचारियों, बीएसएनएल कर्मचारियों और अन्य द्वारा हड़ताल और आंदोलन में साफ दिखायी दी है। ये सभी आत्मनिर्भर भारत के स्तंभ के रूप में सार्वजनिक क्षेत्र की रक्षा के लिए हैं।

मोदी सरकार का 'आत्मानिर्भर भारत '

मोदी सरकार ने विकास की सुनियोजित प्रक्रिया को छोड़ दिया है, जो कि बॉम्बे प्लान और 'स्वाबलम्बी–भारत' का मूल है; सरकारी जिम्मेदारी के बजाय पूरे आर्थिक विकास को बाजार की ताकतों पर छोड़ देना; निजी हाथों में; और न केवल नव उपनिवेशवाद के इस चरण में एफडीआई के रास्ते से षाही पूँजी को आमंत्रित करना, न केवल सार्वजनिक क्षेत्र को बल्कि स्वदेशी निजी क्षेत्र के उद्योगों के अधिग्रहण के लिए भी है। यह संदेश दिया गया है कि भारत में जनता की सम्पत्ति और उसके प्राकृतिक संसाधन जैसे कोयला और तेल, अन्य खनिज मोदी शासन के तहत बिक्री के लिए हैं। हम याराना पूँजीवाद के नंगे नाच को भी देख रहे हैं।

मोदीजी ने 'आत्मानिर्भर भारत' परियोजना के लिए कुछ कदम उठाए हैंः

सभी रणनीतिक और महत्वपूर्ण क्षेत्रों में पीएसईज के बारे मेंः कई सार्वजनिक उद्यमों (पीएसईज) बंद हैं और पहले से ही बिक्री के लिए अधिसूचित हैं। नीति आयोग ने शेष पीएसईज की रणनीतिक या कुल बिक्री की सूची तैयार की है। इसमें प्राकृतिक संसाधन शामिल हैं।

संचार क्षेत्र मेंः एयरवेज के निजीकरण के लिए, एयर इंडिया को बिक्री के लिए अधिसूचित किया गया है और हवाई अड्डों का निजीकरण किया जा रहा है; **रोडवेज** के लिए, मोटर वाहन अधिनियम में संशोधन किया गया है; **जलमार्ग** के लिए, पोर्ट और डॉक कानून बदले जा रहे हैं; **रेलवे** के लिए, निजी हाथों में ट्रेनों को सौंपना, उसकी उत्पादन इकाइयों और कार्यशालाओं का निगमीकरण, रेल स्टेशनों को निजी हाथों में सौंपना।

प्रतिरक्षा क्षेत्र मेंः निजीकरण के लिए प्रतिरक्षा उत्पादन इकाइयों का निगमीकरण, कुछ निर्माणों को आउटसोर्स करना; सार्वजनिक क्षेत्र की एयरोनॉटिक्स उत्पादन इकाई की अनदेखी करके, भारतीय वायु सेना के लिए निजी क्षेत्र के साथ राफेल सौदा।

वित्तीय क्षेत्र मेंः एलआईसी को विनिवेश के लिए सूचीबद्ध किया जा रहा है; सार्वजनिक क्षेत्र की जनरल इन्श्योरेन्स कम्पनियों को सेबी में सूचीबद्ध करने के लिए विलय किया जा रहा है; निजी क्षेत्र के बैंकों के प्रकट हुए भ्रष्टाचारों के बावजूद उनकी मदद करने के लिए, सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों (पीएसबीज) का इनकी षाखाओं को बंद करने के लिए विलय किया जा रहा है और कर्मचारियों की संख्या में भारी कटौती की जा रही है; पीएसबीज को अपने ऋणों को बट्टेखाते में डालने और कुछ भुगतानों को पुनर्निर्धारित करके दुराग्रही कॉरपारेरट बकायेदारों की सेवा करने के लिए मजबूर किया जाता है।

स्वास्थ्य क्षेत्र मेंः भारत में निजी स्वास्थ्य सेवा का रास्ता अपनाने के लिए, हाशिए पर पड़े तबकों के लिए 2018 में बीमा–आधारित **पीएम–जेएवाई** और अन्य लोगों के लिए 2020 में **एनडीएचएम** की षुरुआत करके मुफ्त सार्वभौमिक जन स्वास्थ्य व्यवस्था के रास्ते को ही पूरी तरह से बदल दिया गया है। एफडीआई मार्ग से चिकित्सा शिक्षा और पद्धतियों के विदेशी अधिग्रहण के लिए, 2020 की शुरुआत में ही मेडिकल काउंसिल ऑफ इंडिया (एमसीआइ) को राष्ट्रीय चिकित्सा आयोग द्वारा प्रतिस्थापित किया गया है। और ऑटोमैटिक रास्ते 100 प्रतिशतः एफडीआई के माध्यम से दवाओं का उत्पादन बहुराष्ट्रीय कम्पनियों को सौंपा जा रहा है।

शिक्षा क्षेत्र मेंः निजीकरण, व्यावसायीकरण और साम्प्रदायिकरण अभियान के लिए एनईपी शुरू किया गया है; आईआईटीज के प्रवेश और प्रबंधन को बदला जा रहा है; नैगमिक नीति, सांप्रदायिकता और लोकतांत्रिक मानदंडों के दमन के लिए केंद्रीय विष्वविद्यालयों के चारित्रिक स्वरुप को प्रबंधन नीति के माध्यम से बदला जा रहा है।

यहाँ तक कि सरकारी नौकरियों को आउटसोर्स किया जा रहा है और रणनीतिक प्रशासनिक पदों पर निजी क्षेत्र का प्रवेश किया जा रहा है।

हाथरस सामूहिक बलात्कार के खिलाफ बीएसएनएल कर्मियों का विरोध

चंढ़ीगढ़

लुधियाना, पंजाब

रेवाड़ी, हरियाणा

नागरकोईल, तमिलनाडु

विजयवाड़ा,ए.पी.

कोलकाता,पं०बंगाल

बीएसएनएल वर्किंग वुमन कोऑर्डिनेशन कमेटी (बीएसएनएल डब्ल्यूडब्ल्यूसीसी), बीएसएनएल इम्प्लाइज यूनियन की एक उप–समिति, ने 9 अक्टूबर को हाथरस में एक दलित लड़की के साथ सामूहिक बलात्कार और हत्या के विरोध में पूरे देश में लंच अवकाश के दौरान प्रदर्शन किया। बीएसएनएलईयू के आह्वान पर अन्य कर्मचारी भी शामिल हुए।

आह्वान पर अच्छी प्रतिक्रिया हुई। प्रदर्शनकारियों ने अपराधियों पर कड़ी कार्रवाई की माँग करते हुए, जिस तरह से उन्होंने अपराध को छुपाने की कोषिष की, उसके लिए योगी आदित्यनाथ सरकार के साथ–साथ उत्तर प्रदेश पुलिस की भी निंदा की। उन्होंने लोकतांत्रिक ताकतों द्वारा अपराध के खिलाफ उठाई गई आवाजों को दबाने के लिए उत्तर प्रदेश सरकार और पुलिस की भी निंदा की।

(पृष्ठ 28 से क्रमशः)

डब्ल्यूएफटीयू की 75वीं वर्षगांठ का जश्न

उत्तर प्रदेश

लखनऊ

जौनपुर

Posted at NDPSO New Delhi-1 Postal Regd. No. DL(C)-01/1201/18-2020 RNI No. 34666/79: 6th-7th of every month
Licensed to Post without prepayment under License No.U(C)-38/2018-20 (Date of Publication - 05/11/2020)

डब्ल्यूएफटीयू की 75वीं वर्षगांठ का जश्न

3 अक्टूबर, 2020

केरल

केरल के सभी जिलों में डब्ल्यूएफटीयू की 75वीं वर्षगांठ को मनाया गया। सीटू के राज्य कमेटी कार्यालय पर इसके महासचिव इलामारम करीम ने ट्रेड यूनियन आन्दोलन में आज डब्ल्यूएफटीयू की प्रासंगिकता पर अपनी बात रखी। कोविद प्रतिबन्धों के कारण बड़ी लामबन्दी का आयोजन नहीं किया गया।

आन्ध्र प्रदेश

7 जिलों में, सीटू और एटक के नेतागण और मजदूरों ने प्रदर्शनों के आयोजन में भाग लिया और एक हाल मीटिंग d j d sMCY; ¡wQVh; wd h 75वीं वर्षगांठ को मनाया गया।

ओड़िशा

दिवस का आयोजन सीटू, एटक, एआईयूटीयूसी, एआईसीसीटीयू और एआईबीईए ने संयुक्त रुप से राज्य की राजधानी भुवनेश्वर में मास्टर कैन्टीन चौक पर किया गया और साम्राज्यवाद के खिलाफ और समाजवाद के लिए डब्ल्यूएफटीयू के नारे लगाए।*(पृष्ठ 27 से क्रमशः)*

तपन सेन द्वारा सेंटर ऑफ इण्डियन ट्रेड यूनियन्स के लिए मुद्रित और प्रकाशित तथा प्रोग्रैसिव प्रिंटर्स, ए–21 झिलमिल इण्डस्ट्रियल एरिया, शाहदरा, दिल्ली–95 से मुद्रित तथा बी टी रणदिवे भवन, 13–ए राउज एवेन्यू, नई दिल्ली–110002 से प्रकाशित (फोनः 23221288, 23221306; http://www.citucentre.org, CITU email: citu@bol.net.in, citubtr@gmail.com) सम्पादक : के हेमलता